

[2023] 5 एस. सी. आर. 1016

सुंदर @सुंदरराजन

वी.

पुलिस निरीक्षक द्वारा कथन

(समीक्षा याचिका (सी. आर. एल.) नं. 159-160 2013 का)

में।

(अपराधिक अपील सं। 300-301 2011 का)

21 मार्च, 2023

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई,

हिमा कोहली और पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा,

जे. जे.]

भारत का संविधान: कलाएँ। 137 - में अधिकार क्षेत्र की समीक्षा करें

मृत्युदंड से संबंधित मामले-याचिकाकर्ता का दायरा

7 साल के बच्चे के अपहरण और हत्या का आरोपी

इसके खिलाफ-परिसंचरण के माध्यम से खारिज किया गया-हालांकि, को देखते हुए मोहम्मद में निर्णय। आरिफ का मामला, परिसंचरण के माध्यम से समीक्षा याचिका को खारिज करने का आदेश वापस ले लिया गया और याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई हुई

आयोजित किया गया: उठाए गए आधारों में से कोई भी रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटियों के बराबर नहीं है- सभी आधार अभियोजन मामले में कोई उचित संदेह पैदा करने में विफल रहते हैं-इस प्रकार, निचली अदालत, उच्च न्यायालय और इस अदालत के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

पीड़ित की हत्या-भले ही अपराध द्वारा किया गया हो

याचिकाकर्ता निर्विवाद रूप से गंभीर और अक्षम्य है, उसे दी गई मौत की सजा की पुष्टि करना उचित नहीं है

-

दुर्लभ 'सिद्धांत की आवश्यकता है कि मृत्युदंड केवल अपराध की गंभीर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए नहीं दिया जाए, बल्कि केवल तभी दिया जाए जब किसी अपराधी में सुधार की कोई संभावना न हो-किसी भी अपीलीय अदालत के समक्ष कोई कम करने वाली परिस्थितियां नहीं रखी गईं-यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने एक भयानक अपराध किया है, हालांकि सुधार की कोई संभावना नहीं है-साथ ही यह भी कहा गया था कि सुनवाई निचली अदालत में अलग से नहीं की गई थी-इस प्रकार, 7 साल के बच्चे की हत्या के अपराध की वीभत्स प्रकृति को देखते हुए, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है।

1016 सुंदर @सुंदरराजन बनाम। निरीक्षक द्वारा कथन

पुलिस

बिना किसी छूट या छूट के कम से कम बीस वर्षों के लिए

-

उच्चतम न्यायालय नियम 2013-अध्यादेश। XLVII r. 1 .

सजा/सजा:

स्थितियों को कम करना

मृत्युदंड

-

सजा पर निर्णय लेते समय विचार-आयोजित: कर्तव्य

न्यायालय का कम करने वाली परिस्थितियों की जांच करने के साथ-साथ

मृत्युदंड देने से पहले सुधार और पुनर्वास की संभावना को बंद कर दें-राज्य को सभी सामग्री को समान रूप से रखना चाहिए।

और अभिलेख पर स्थित परिस्थितियाँ सुधार की संभावना पर असर डालती हैं

ऐसी कई सामग्रियाँ और पहलू ज्ञान के दायरे में हैं

ऐसा राज्य जिसकी अभियुक्त की अभिरक्षा पहले और बाद में दोनों समय में रही हो

दोषसिद्धि-इसके अलावा, न्यायालय इसके प्रति उदासीन नहीं हो सकता है

प्रक्रिया में स्थिति-अदालत की प्रक्रिया और शक्तियाँ हो सकती हैं

इसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि ऐसी सामग्री को सुधार की संभावना के आधार पर न्यायसंगत सजा का निर्णय लेने के लिए उपलब्ध कराया जाए।

बिगड़ती परिस्थितियाँ

मृत्युदंड

दण्डादेश पर निर्णय लेते समय विचार: लिंग

बच्चे को अपने आप में उत्तेजक नहीं माना जा सकता है।
गंभीर अपराध है और

परिस्थिति-एक छोटे बच्चे की हत्या एक

पीड़ित की कम उम्र के साथ-साथ पूरे परिवार को होने वाला आघात अपने आप में एक भयावह परिस्थिति है-ऐसा नहीं है और

संवैधानिक अदालत के लिए यह मायने नहीं रखना चाहिए कि छोटा बच्चा पुरुष था या महिला-अदालतों को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए।

इस धारणा को आगे बढ़ाते हुए कि केवल एक पुरुष बच्चा ही पारिवारिक वंशावली को आगे बढ़ाता है या वृद्धावस्था में माता-पिता की सहायता करने में सक्षम होता है-इस तरह की टिप्पणी अनैच्छिक रूप से की जाती है।

आगे पितृसत्तात्मक मूल्य निर्णय जिनसे अदालतों को बचना चाहिए।

साक्ष्य अधिनियम, 1972: एस. 65 बी-में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य

कॉल विवरण रिकॉर्ड का रूप-सी. डी. आर.-एक प्रमाण पत्र का उत्पादन यू / धारा 65 बी, यदि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को स्वीकार करने के लिए अनिवार्य है-आयोजित: एस. 65 बी प्रमाणपत्र अनिवार्य है-तथ्यों पर, समीक्षा याचिका होगी

सी. डी. आर. के रूप में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को छोड़ने पर विचार किया गया

क्योंकि वे उपयुक्त प्रमाणपत्र यू/एस के बिना हैं। 65 बी.

न्यायालय की अवमानना: भौतिक तथ्यों का खुलासा न करना

-

दाखिल किए गए शपथपत्र में, भौतिक रूप से जानकारी को रोक दिया गया
कारागार में याचिकाकर्ता का आचरण इस प्रकार,

न्यायालय से

दोषी के खिलाफ सुओ मोटू अवमानना कार्यवाही शुरू करना।

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पुनरीक्षण याचिकाओं का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पी. डब्ल्यू. 1 और पी. डब्ल्यू. 8 के बयानों के माध्यम से दिया गया। उन दोनों का गवाही की पुष्टि न केवल सी. डी. आर. के माध्यम से की जाती है, बल्कि

याचिकाकर्ता के इकबालिया बयान के आधार पर मोबाइल फोन की वसूली के माध्यम से भी। भले ही पूर्व पी5, सी. डी. आर. होने के नाते, इस न्यायालय द्वारा भरोसा नहीं किया जाता है, अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर नहीं है क्योंकि यह केवल दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों की गवाही की पुष्टि करता है जो शेष हैं।

बिना किसी परवाह के बेदाग। इसे ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के अपराध पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए, भले ही याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधारों में से कोई भी रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटियों के बराबर नहीं है, लेकिन इसे देखते हुए, यह

पीडित के अपहरण और हत्या के लिए याचिकाकर्ता के अपराध के संबंध में निचली अदालत, उच्च न्यायालय और इस अदालत के समवर्ती निष्कर्ष। [पैरा 52-54] [1048-E-F; 1049-F-H] 1.2 याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ऐसे मामलों में मौत की सजा नहीं दी जा सकती है जहां दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो।

अभियुक्त के अपराध के बारे में संदेह बना रहता है। अवशिष्ट या विलंबित संदेह का तर्क याचिकाकर्ता के बचाव में नहीं आता है। [पैरा 57,59] [1050-सी-डी] 1.3 यह न्यायालय पहले ही परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में अपील में याचिकाकर्ता के अपराध की पुष्टि करने के लिए प्रासंगिक मानक लागू कर चुका है और इस न्यायालय के लिए अपने सीमित दायरे को देखते हुए समीक्षा अधिकार क्षेत्र में साक्ष्य के मूल्यांकन में एक बार फिर प्रयास करना उचित नहीं होगा।

[पैरा 60] [1051-एफ-जी]

1.4 तत्काल मामले में, सजा सुनाने से संबंधित निचली अदालत का निर्णय इंगित करता है कि एक सार्थक, वास्तविक और प्रभावी

याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था। निचली अदालत ने सजा सुनाने पर कोई अलग सुनवाई नहीं की और याचिकाकर्ता सुंदर @सुंदरराजन बनाम से संबंधित किसी भी कम करने वाली परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा।

निरीक्षक द्वारा कथन

पुलिस

मृत्युदंड देने से पहले। उच्च न्यायालय ने इस कृत्य की वीभत्स और निर्दयी प्रकृति को ध्यान में रखा। इसने उन उदाहरणों को दोहराया जिसमें कहा गया था कि मृत्युदंड केवल दुर्लभतम मामलों में ही दिया जाना है। हालाँकि, इसने विशेष रूप से याचिकाकर्ता पर असर डालने वाली किसी भी कम करने वाली परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया। इस न्यायालय ने अपराध की बढ़ती परिस्थितियों की विस्तार से जांच की। उपरोक्त अनुक्रम इंगित करता है कि याचिकाकर्ता को मृत्युदंड की सजा दिए जाने के बावजूद मुकदमे या अपीलीय प्रक्रिया के किसी भी चरण में याचिकाकर्ता की किसी भी कम करने वाली परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा गया था। [पैरा 70-74] [1056-बी-सी, एफ-जी; 1057-ए, डी]

1.5 इस न्यायालय द्वारा अपील में जिन गंभीर परिस्थितियों पर ध्यान दिया गया था, उनके संदर्भ में कुछ परिस्थितियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। यह ध्यान दिया जाता है कि बच्चे के लिंग को अपने आप में एक उत्तेजक परिस्थिति नहीं माना जा सकता है।

संवैधानिक न्यायालय। एक छोटे बच्चे की हत्या

निर्विवाद रूप से एक गंभीर अपराध और इस तरह के पीड़ित की कम उम्र के साथ-साथ पूरे परिवार के लिए जो आघात पैदा करता है, वह निस्संदेह एक भयावह परिस्थिति है। ऐसी परिस्थिति में, संवैधानिक न्यायालय के लिए यह मायने नहीं रखता कि छोटा बच्चा पुरुष बच्चा था या महिला बच्चा। हत्या भी उतनी ही दुखद बनी हुई है। अदालतों को इस धारणा को आगे बढ़ाने में भी शामिल नहीं होना चाहिए कि केवल एक पुरुष बच्चा ही पारिवारिक वंशावली को आगे बढ़ाता है या वृद्धावस्था में माता-पिता की सहायता करने में सक्षम होता है। इस तरह की टिप्पणियाँ अनैच्छिक रूप से पितृसत्तात्मक मूल्य वाले निर्णयों को आगे बढ़ाती हैं जो अदालतों को

संदर्भ की परवाह किए बिना बचना चाहिए। [पैरा 75] [1057-ई, एच; 1058-ए-सी]

1.6 याचिकाकर्ता के मामले में उल्लिखित कारकों पर विचार करने के लिए कोई जांच नहीं की गई थी। न ही ट्रायल कोर्ट, और न ही अपीलीय अदालतों ने निर्णायक रूप से यह कहने के लिए किसी भी कारक पर ध्यान दिया है कि याचिकाकर्ता में सुधार या पुनर्वास नहीं किया जा सकता है। अदालतों ने वीभत्स प्रकृति को दोहराया है

मृत्युदंड देने के लिए अपराध। अपील में, इस न्यायालय ने केवल यह उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता के वकील परिस्थितियों को कम करने की ओर इशारा नहीं कर सके और मौत की सजा को बरकरार रखा। राज्य को सुधार की संभावना से संबंधित सभी सामग्री और परिस्थितियों को समान रूप से रिकॉर्ड पर रखना चाहिए। ऐसी कई सामग्री और पहलू राज्य की जानकारी में हैं जिनके पास दोषी ठहराए जाने से पहले और बाद में आरोपी की अभिरक्षा थी।

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसके अलावा, अदालत इस प्रक्रिया में उदासीन नहीं हो सकती है। न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है -

यह सुनिश्चित करें कि सुधार की संभावना को ध्यान में रखते हुए न्यायसंगत सजा का निर्णय लेने के लिए ऐसी सामग्री उपलब्ध कराई जाए। [पैरा 79] [1061-डी-एफ]

1.7 अदालत का कर्तव्य है कि वह कम करने की जांच करे

इस न्यायालय के कई निर्णयों में परिस्थितियों के साथ-साथ मृत्युदंड देने से पहले सुधार और पुनर्वास की संभावना को उजागर किया गया है। इसके बावजूद, वर्तमान मामले में ऐसी कोई जांच नहीं की गई थी और मौत की सजा देते समय अपराध की गंभीर प्रकृति पर ही विचार किया गया था। [पैरा 81] [1062-एच; 1063-ए]

1.8 तथ्य यह है कि किसी भी अपीलिय अदालत के समक्ष कोई कम करने वाली परिस्थितियाँ नहीं रखी गई। यह नहीं कहा जा सकता कि सुधार की कोई संभावना नहीं है, भले ही याचिकाकर्ता ने एक भयानक अपराध किया हो। कम करने वाले कारक कि याचिकाकर्ता का कोई पूर्व इतिहास नहीं है, जब उसने अपराध किया था तब उसकी आयु 23 वर्ष थी और वह 2009 से जेल में है।

भागने के प्रयास को छोड़कर उसका आचरण संतोषजनक रहा है।

2013 में जेल; कि याचिकाकर्ता प्रणालीगत उच्च रक्तचाप के मामले से पीड़ित है और उसने खाद्य खानपान में डिप्लोमा के रूप में कुछ बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास किया है; कि जेल में एक व्यवसाय के अधिग्रहण का लाभप्रद जीवन जीने की उसकी क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए, भले ही याचिकाकर्ता द्वारा किया गया अपराध निर्विवाद रूप से गंभीर और अक्षम्य है, यह उचित नहीं है

उसे दी गई मौत की सजा की पुष्टि करने के लिए। 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' सिद्धांत के लिए आवश्यक है कि मौत की सजा केवल अपराध की गंभीर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए नहीं दी जाए, बल्कि केवल तभी दी जाए जब किसी अपराधी में सुधार की कोई संभावना न हो। हालाँकि, न्यायालय इस बात से भी अवगत है कि आजीवन कारावास की सजा माफी के अधीन है। याचिकाकर्ता द्वारा किए गए वीभत्स अपराध को देखते हुए यह पर्याप्त नहीं होगा। [पैरा 88-90] [1064-E-H; 1065 A]

1.9 पीड़ित के अपहरण और हत्या में याचिकाकर्ता के अपराध पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। का अभ्यास

दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने के लिए समीक्षा में अधिकार क्षेत्र आवश्यक नहीं है। हालाँकि, न्यायालय सुनदार @सुनदराजन बनाम की दलीलों पर ध्यान देता है।

निरीक्षक द्वारा कथन

पुलिस

निचली अदालत में अलग से सजा सुनाने की सुनवाई नहीं की गई और याचिकाकर्ता को मृत्युदंड देने से पहले अपीलीय अदालतों में परिस्थितियों को कम करने पर विचार नहीं किया गया। इसका वजन करते समय

तर्क के अनुसार, केवल 7 वर्ष की आयु के एक छोटे बच्चे की हत्या के अपराध की वीभत्स प्रकृति ने भी न्यायालय पर भार डाला है और न्यायालय को यह नहीं लगता है कि आजीवन कारावास की सजा,

जो आम तौर पर 14 साल की अवधि तक काम करता है, परिस्थितियों में अनुपातिक होगा। तदनुसार, याचिकाकर्ता पर लगाई गई मौत की सजा को बिना किसी राहत या छूट के बीस साल से कम के लिए आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है। [पैरा 93,94] [1066-बी-ई]

1.10 अलग से, पुलिस निरीक्षक, कम्मपुरम पुलिस स्टेशन, कुड्डालोर को एक नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है।

जिला, तमिलनाडु राज्य 26 सितंबर 2021 को शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए, इसका स्पष्टीकरण देगा। इस मामले में, प्रथम दृष्टया, जेल में याचिकाकर्ता के आचरण के बारे में भौतिक जानकारी इस अदालत से छिपी हुई थी। तदनुसार, रजिस्ट्री को अदालत की अवमानना के लिए मामले को स्वतः संज्ञान कार्यवाही के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है। [पैरा 95] [1066-एफ]

मोहम्मद. आरिफ उर्फ अशफाक बनाम पंजीयक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय 2014 (9) एस. सी. सी. 737: [2014] 11 एससीआर 1009 -

पीछा किया।

मोफिल खान बनाम झारखंड राज्य 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइनएससी 1136; अर्जुन पंडितराव खोटकर बनाम कैलाश कुषाणराव

गोरंट्याल 2020 (7) एस. सी. सी. 1; अनवर पी. वी. बनाम पी. के. बशीर

2014 (10) एससीसी 473: [2014] 11 एससीआर 399; राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम नवजोत संधू 2005 (11) एस. सी. सी. 600: [2005] 2 पूरका एस. सी. आर. 79; टोमासो ब्रूनो बनाम उत्तर राज्य

प्रदेश 2015 (7) एससीसी 178: [2015] 1 एस. सी. आर. 721; शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 2018 (2) एस. सी. सी. 301; सोनू उर्फ अमर बनाम हरियाणा राज्य 2017 (8) एस. सी. सी. 570 [2017] 8 एस. सी. आर. 151; मोहम्मद. आरिफ बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1509; शत्रुघ्न बबन मेशराम बनाम महाराष्ट्र राज्य 2021 (1) एस. सी. सी. 596; सांता सिंह बनाम पंजाब राज्य 1976 (4) एस. सी. सी. 190: [1977] 1 एससीआर 229; बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य [2023] 5 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1980 (2) एस. सी. सी. 684; मुनियप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य

1981 (3) एससीसी 11: [1981] 3 एससीआर 270; अलाउद्दीन मियां

बनाम बिहार राज्य 1989 (3) एससीसी 5: [1989] 2 एससीआर 498;

अंगुस्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य 1989 (3) एस. सी. सी. 33;
मलकियत सिंह बनाम पंजाब राज्य 1991 (4) एस. सी. सी. 341:

[1991] 2 एस. सी. आर. 256; दत्तराय बनाम महाराष्ट्र राज्य

2020 (14) एससीसी 290: [2019] 11 एस. सी. आर. 295; डागडू बनाम
महाराष्ट्र राज्य 1977 (3) एससीसी 68: [1977] 3 एससीआर

636 ; तरलोक सिंह बनाम पंजाब राज्य 1977 (3) एससीसी 218
: [1977] 3 एस. सी. आर. 711; रामदेव चौहान बनाम असम राज्य

2001 (5) एससीसी 714: [2001] 3 एससीआर 669; पुनः: फ्रेमिंग

संभावित शमन के संबंध में दिशानिर्देश
मृत्यु अधिरोपित करते समय जिन परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए

वाक्य सुओ मोटू डब्ल्यू. पी. (सीआरएल) नं. 1/2022; राजेन्द्र
प्रल्हादराव वासनिक बनाम महाराष्ट्र राज्य 2019 (12)

एससीसी 460 [2018] 14 एससीआर 585; संतोष कुमार

सतीशभूषण बरियार बनाम महाराष्ट्र राज्य 2009
(6) एससीसी 498: [2009] 9 एससीआर 90; अनिल बनाम स्टेट ऑफ

महाराष्ट्र 2014 (4) एससीसी 69 [2014] 3 एससीआर 34;

स्वामी श्रद्धानंद (2) @मुरली मनोहर मिश्रा

बनाम कर्नाटक राज्य 2008 (13) एससीसी 767-निर्दिष्ट

को।

राजधानी मामलों में समीक्षा क्षेत्राधिकार का प्रयोग

मृत्युदंड और भारतीय सर्वोच्च

न्यायालय (2007-2021), परियोजना 39 ए, राष्ट्रीय कानून
दिल्ली विश्वविद्यालय (2022)-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2014] 11 एससीआर 1009

पीछा किया।

पै

रा 1

(2020) 7 एससीसी 1

संदर्भित किया गया है

पै

रा 30

[2014] 11 एससीआर 399

संदर्भित किया गया है

पै

रा 30

[2005] 2 पूरक। एससीआर 79

पै

रा 31

संदर्भित किया गया है

[2015] 1 एससीआर 721

संदर्भित किया गया है

पै

रा 34

(2018) 2 एस. सी. सी. 801

संदर्भित किया गया है

पै

रा 35

[2017] 8 एससीआर 151

संदर्भित किया गया है

रा 40

(2021) 1 एस. सी. सी. 596

संदर्भित किया गया है

पैरा 58 सुंदर @सुंदरराजन बनाम। निरीक्षक सी द्वारा कथन

पुलिस

[1977] 1 एससीआर 229

संदर्भित किया गया है

पै

रा 63

(1980) 2 एस. सी. सी. 684

पै

रा 64

संदर्भित किया गया है

[1981] 3 एससीआर 270

पै

रा 65

संदर्भित किया गया है

[1989] 2 एससीआर 498

संदर्भित किया गया है

पै

रा 66

(1989) 3 एससीसी 33

पै

रा 67

संदर्भित किया गया है

[1991] 2 एससीआर 256

संदर्भित किया गया है

पै

रा 67

[2019] 11 एससीआर 295

रा 67

पै

संदर्भित किया गया है

[1977] 3 एससीआर 636

संदर्भित किया गया है

रा 68

पै

[1977] 3 एससीआर 711

संदर्भित किया गया है

रा 68

पै

[2001] 3 एससीआर 669

रा 68

पै

संदर्भित किया गया है

[2018] 14 एससीआर 585

रा 76

पै

संदर्भित किया गया है

[2009] 9 एससीआर 90

रा 77

पै

संदर्भित किया गया है

[2014] 3 एससीआर 34

संदर्भित किया गया है

रा 78

पै

(2008) 13 एस. सी. सी. 767

संदर्भित किया गया है

पै

रा 91

अंतर्निहित न्यायनिर्णय: समीक्षा याचिका (सी. आर. एल.) नं.

160 2013 का 2011 की आपराधिक अपील Nos.300-301 में।

सीआरएल में 15.02.2013 दिनांकित निर्णय और आदेश से। ए. संख्या

और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का 2011 का 301।

रंजीत बी. मरार, सुश्री लक्ष्मी एन. कैमल, अरुण पूनावली,

संतोष, एड. याचिकाकर्ता के लिए।

बी. कृष्णमूर्ति, ए. ए. जी., डॉ. जोसेफ अरस्तू एस., सुश्री एन.

शर्मा, शोभित द्विवेदी, संजीव कुमार महारा, सुश्री आर विश्वकर्मा, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई

इस निर्णय में निम्नलिखित खंड शामिल हैं:

ए. प्रस्तावना-मोहम्मद का प्रभाव। आरिफ।

बी.

पृष्ठभूमि

समीक्षा क्षेत्राधिकार का दायरा

सी.

* एड। ध्यान दें: पृष्ठांकन मूल निर्णय के अनुसार है।

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अभिलेख के सामने स्पष्ट त्रुटि? 10 *

डी.

..... 10 *

D. 1 वकील की प्रस्तुतियाँ।

डी. 2. विश्लेषण करें।

..... 12 *

सजा और शमन।

..... 32 *

ई.

... 32 *

ई. 1. अनिश्चित संदेह सिद्धांत।

ई. 2. विचारण न्यायालय में सजा और शमन और

अपीलीय न्यायालय।

..... 34 *

एफ.

निष्कर्ष।

..... 50 *

1. आवेदक मौत की सजा का दोषी है। उन्होंने इसे स्थानांतरित कर दिया है

हत्या के अपराध के लिए उनकी दोषसिद्धि की समीक्षा और मौत की सजा की मांग करने वाली उनकी याचिका पर नए सिरे से विचार करने के लिए अदालत। वह जल्द ही मोहम्मद में संविधान पीठ के फैसले का

आधार बनाता है। आरिफ उर्फ अशफाक बनाम पंजीयक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय 1. मोहम्मद में। आरिफ, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि दोषसिद्धि और मृत्युदंड के अधिरोपण से उत्पन्न समीक्षा याचिकाओं की सुनवाई खुली अदालत में की जानी चाहिए और इसका निपटान परिसंचरण द्वारा नहीं किया जा सकता है। संविधान पीठ ने उन याचिकाकर्ताओं को फैसले की तारीख से एक महीने की अवधि की अनुमति दी, जिनके आवेदनों में इस अदालत के फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी, जिसमें मौत की सजा की पुष्टि की गई थी, जिन्हें प्रचलन द्वारा खारिज कर दिया गया था, जहां सजा अभी तक निष्पादित नहीं की गई थी।

ए. प्रस्तावना-मोहम्मद का प्रभाव। आरिफ

2. मोहम्मद में। आरिफ, इस अदालत ने अपरिवर्तनीय प्रकृति पर ध्यान दिया

मृत्युदंड और मृत्युदंड के अधिनिर्णय के लिए किसी मामले के उपयुक्त होने के प्रश्न पर दो न्यायिक दिमागों के अलग-अलग निष्कर्ष पर पहुंचने की संभावना। बहुमत के निर्णय ने मृत्युदंड से जुड़े मामलों की समीक्षा में मौखिक सुनवाई के अधिकार की अनुमति दी:

29. [.....] मृत्युदंड के मामले मामलों की एक अलग श्रेणी है। कुल मिलाकर। संविधान के अनुच्छेद 134 के अलावा

सभी मौतों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का एक स्वचालित अधिकार सजा के मामले, और केवल मौत की सजा के अलावा

दुर्लभतम मामलों में, दो कारकों ने हमें प्रभावित किया है। द.

सबसे पहले मृत्युदंड की अपरिवर्तनीयता है। और दूसरा

यह तथ्य है कि विभिन्न न्यायिक रूप से प्रशिक्षित दिमाग आ सकते हैं निष्कर्षों पर जो, समान तथ्यों पर, पूर्ण रूप से हो सकते हैं

* एड। ध्यान दें: पृष्ठांकन मूल निर्णय के अनुसार है।

1 2014 (9) एस. सी. सी. 737 एन. डी. ए. आर @सुंदरराजन बनाम। पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई]

एक-दूसरे के खिलाफ। ऊपर उल्लिखित दूसरे कारक पर ध्यान देते हुए, यह सर्वविदित है कि मृत्युदंड के फैसले को वापस करने के पीछे मूल सिद्धांत यह है कि इसे दुर्लभतम मामलों में दिया जाना है। वहाँ उत्तेजक और साथ ही शमनकारी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनकी अदालत द्वारा जांच की जानी है। साथ ही, यह निर्धारित करने के लिए सिद्धांत निर्धारित करना संभव नहीं है कि कौन सा मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आएगा, जिससे मौत की सजा को उचित ठहराया जा सके। इस तरह के प्रश्न पर पहुँचते समय सटीक रूप से मापदंडों या उग्र/शमनकारी परिस्थितियों का उल्लेख करना भी आसान नहीं है जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। यद्यपि विभिन्न मामलों में न्यायाधीशों द्वारा ऐसी परिस्थितियों को बताने के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन वे केवल उदाहरणात्मक ही रहते हैं।

30. [.....] सजा कई कारकों का एक यौगिक है, जिसमें अपराध की प्रकृति के साथ-साथ अपराध को बढ़ाने या बढ़ाने वाली परिस्थितियाँ शामिल हैं। बड़ी संख्या में उग्रता

बचन सिंह बनाम में परिस्थितियों और कम करने वाली परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है। पंजाब राज्य, एस. सी. सी. पीपी. 749-50 , पैरा 202 और 206, कि एक न्यायाधीश को मृत्युदंड देते समय ध्यान में रखना चाहिए। फिर से, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस तथ्य के अलावा कि ये सूचियाँ केवल उदाहरणात्मक हैं, जैसा कि बचन सिंह में ही स्पष्ट किया गया है, विभिन्न न्यायिक रूप से प्रशिक्षित दिमाग अंततः किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए विभिन्न उत्तेजक और शमनकारी परिस्थितियों को लागू कर सकते हैं, उन सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने पर जो किसी भी मामले में मृत्युदंड दिया जा सकता है या नहीं भी जा सकता है। इस पहलू को व्यापक रूप से छूने वाले न्यायिक निर्णयों पर आधारित अनुभव

इस तरह के एक अलग दृष्टिकोण को प्रदर्शित करें।

हालाँकि, इस पहलू पर विस्तार से ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, साथ ही, इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि जब तथ्यों के एक ही समूह पर, एक न्यायिक दिमाग इस निष्कर्ष पर आ सकता है कि परिस्थितियाँ नहीं हैं।

मृत्युदंड का आदेश देता है, जबकि कोई अन्य इसे पूरी तरह से मृत्युदंड को उचित ठहराने वाला एक उपयुक्त मामला मान सकता है, हम महसूस करते हैं कि जब कोई दोषी जिसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है और वह पुनरीक्षण याचिका दायर करता है, तो ऐसी पुनरीक्षण याचिका में मौखिक सुनवाई की आवश्यकता "उचित प्रक्रिया" का एक अभिन्न अंग बन जाती है।

(जोर दिया गया)

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. प्रोजेक्ट 39 ए द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में सभी निर्णयों की जांच की गई

इसमें 2007 और 2021 के बीच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई मौत की सजा शामिल है, जिसके हिस्से के रूप में उसने राजधानी के मामलों में समीक्षा क्षेत्राधिकार के प्रयोग का विश्लेषण किया। इसने नोट किया कि, अध्ययन द्वारा कवर की गई अवधि के दौरान, मोहम्मद में निर्णय से पहले। आरिफ, 14 पुनर्विचार याचिकाओं को प्रचलन द्वारा खारिज कर दिया गया और उन सभी में मृत्युदंड की पुष्टि की गई। इनमें से 13 को फैसले को ध्यान में रखते हुए फिर से खोला गया, जिसके परिणामस्वरूप केवल 4 बार मौत की सजा की पुष्टि हुई। दूसरी ओर, 7 फैसलों के परिणामस्वरूप मौत की सजा को कम कर दिया गया, 1 को बरी कर दिया गया और 1 मामले को कैदी की मृत्यु के कारण कम कर दिया गया। उपरोक्त आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, मोहम्मद में फैसले के कारण समीक्षा याचिकाओं की मौखिक सुनवाई का प्रभाव। आरिफ के कारण मृत्युदंड की पुष्टि के परिणाम में बदलाव स्पष्ट है।

4. मोहम्मद में अदालत। हालाँकि, आरिफ द्वारा राजी नहीं किया गया था

उन न्यायाधीशों से परे दो अतिरिक्त न्यायाधीशों को शामिल करने का तर्क जिन्होंने समीक्षा याचिका की सुनवाई के दौरान मूल अपील सुनी थी। इसने यह भी कहा कि समीक्षा की सुनवाई आम तौर पर उसी पीठ द्वारा की जानी चाहिए जिसने मूल रूप से आपराधिक अपील की सुनवाई की थी। इसमें उल्लेख किया गया था कि:

न्यायालय, केवल तीन माननीय न्यायाधीशों की एक पीठ इसकी सुनवाई करेगी। यही कारण है कि कम से कम तीन न्यायिक रूप से प्रशिक्षित मस्तिष्क

एक की यात्रा के अंतिम चरण में अपने दिमाग को लागू करने की आवश्यकता है

मौत की सजा पर दोषी, सजा की अनिश्चितताओं को देखते हुए

ऊपर वर्णित प्रक्रिया। वर्तमान में, हम आश्वस्त नहीं हैं

कम से कम 5 विद्वान न्यायाधीशों को सभी मौतों की सुनवाई करने के लिए

सजा के मामले। इसके अलावा, [...] एक समीक्षा आम तौर पर होनी चाहिए

केवल उसी पीठ द्वारा सुना गया जिसने मूल रूप से सुना था

आपराधिक अपील। यह स्पष्ट रूप से कारण है कि क्रम में

कि एक समीक्षा सफल होती है, अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटियाँ होती हैं ढूँढने के लिए। यह स्वयंसिद्ध है कि वही विद्वान न्यायाधीश

गलती करने का आरोप अब लगाया जाना चाहिए

इस तरह की त्रुटि को ठीक करें। इसलिए हम याचिका को खारिज करते हैं।

कि समीक्षा चरण में दो अतिरिक्त न्यायाधीश जोड़े जाएँ
मृत्युदंड के मामले।

(जोर दिया गया)

2 मृत्युदंड और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय (2007-2021), परियोजना 39 ए, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली (2022) में पूंजीगत मामलों में समीक्षा क्षेत्राधिकार का प्रयोग।

सुंदर @सुंदरराजन बनाम। पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई]

5. परियोजना 39 ए द्वारा विश्लेषण किए गए आंकड़ों से संकेत मिलता है कि यह केवल समीक्षा याचिकाओं की मौखिक सुनवाई नहीं है जिसने परिणामों को बदल दिया है। अंतिम परिणाम बदलने और समीक्षा प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अलग-अलग न्यायाधीशों को शामिल करने के बीच एक सहसंबंध भी हो सकता है, बजाय उन्हीं न्यायाधीशों के जिन्होंने मूल रूप से अपील का फैसला किया था। पोस्ट मोहम्मद। आरिफ, ऐसा तब होता है जब न्यायाधीश जो मूल पीठ के सदस्य थे, उस समय तक पद छोड़ चुके होते हैं जब खुली अदालत की समीक्षा आती है।

समीक्षा के चरण को बहुमत द्वारा परिकल्पित उद्देश्य के लिए लगभग अनावश्यक बना दिया गया है, यानी एक और पुनर्विचार। मृत्युदंड की सजा, जब उसी पीठ (आपराधिक अपील के रूप में) को पुनर्विचार याचिका पर निर्णय लेने के लिए बुलाया जाता है। वास्तव में यह

आंकड़ों से पता चलता है। जैसा कि न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी, जब उसी पीठ द्वारा अपील की सुनवाई की गई, तो पुनर्विचार याचिकाओं के परिणामस्वरूप मौत की सजा बरकरार रखी गई। 4 समीक्षा के चरण में दिए गए 11 पुष्टि निर्णयों में से एक ही पीठ थी। जबकि समीक्षा में शेष 7 पुष्टिकरण निर्णय अलग-अलग पीठों द्वारा दिए गए थे, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि इनमें से 1 निर्णय में एक न्यायाधीश समीक्षा और अपील का फैसला करने वाली दोनों पीठों के लिए समान था, और दूसरे में, दो न्यायाधीश दोनों पीठों के लिए समान थे। दूसरी ओर, सभी

10 निर्णय जिनके परिणामस्वरूप समीक्षा चरण में परिवर्तन हुआ, [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

से एक अलग रचना वाले बेंचों द्वारा प्रस्तुत किया गया था पीठ जिसने अपील का फैसला किया। इसलिए, आंकड़ों से पता चलता है कि अपील में दिए गए फैसले के 30 दिनों के भीतर दायर की गई समीक्षा याचिका, एक ही पीठ द्वारा तय की गई, दृष्टिकोण या परिणाम में काफी अंतर प्रदर्शित नहीं करेगी, जैसा कि एक अलग पीठ द्वारा तय किया गया है।

(जोर दिया गया)

7. जबकि उपरोक्त डेटा निर्णायक नहीं है और सहसंबंध हो सकता है

आवश्यक रूप से कारण के बराबर नहीं है, हम इसका उल्लेख करना उचित पाते हैं क्योंकि वर्तमान मामला भी मोहम्मद में निर्णय के परिणामस्वरूप फिर से खोला और फिर से सुना जाने वाले मामलों में से एक है। आरिफ। हम प्रचुरता के माध्यम से स्पष्ट करते हैं

सावधान करें कि एक छोटी पीठ होने के नाते और मौत की सजा की पुष्टि करने वाली अपील की समीक्षा में बैठे विभिन्न न्यायाधीशों के प्रभाव पर विचार करने के लिए नहीं बुलाए जाने के कारण, हम प्रस्ताव के गुण-दोष पर निर्णय नहीं ले रहे हैं।

B. पृष्ठभूमि

8.

मोहम्मद में फैसले को देखते हुए। आरिफ, 20 तारीख का आदेश

मार्च 2013 में वर्तमान मामले में परिसंचरण के माध्यम से समीक्षा याचिका को खारिज करने को वापस ले लिया गया और इस समीक्षा याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई की गई।

9. याचिकाकर्ता पर 7 के अपहरण और हत्या का आरोप लगाया गया था

एक साल का बच्चा। याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसने पीड़ित को 27 जुलाई 2009 को उस समय उठाया था जब वह स्कूल से स्कूल वैन में लौट रहा था। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने याचिकाकर्ता को गवाही दी कि उसने

पीड़ित अपनी मोटरसाइकिल पर।

10. पीड़ित की अनुपस्थिति के कारण, उसकी माँ ने उसे खोजने का प्रयास किया

कहाँ है और एक गवाह द्वारा घटनाओं के उपरोक्त क्रम के बारे में सूचित किया गया था। तदनुसार, वह उसी तारीख को पुलिस स्टेशन, कम्मपुरम में शिकायत दर्ज करने के लिए आगे बढ़ी। उसी रात, उसे याचिकाकर्ता से अपने मोबाइल फोन पर एक कॉल भी आया, जिसमें मांग की गई थी

रुपये की फिरौती। 5 पीड़ित की रिहाई के लिए लाखों। इसके अलावा, अगले दिन एक टेलीफोन बूथ से फिरौती के लिए एक और कॉल किया गया। गवाहों में से एक वह व्यक्ति है जो बूथ चलाता है और उसने गवाही दी है कि याचिकाकर्ता ने पैसे के भुगतान के बारे में पूछताछ करने के लिए फोन किया था।

11. 30 जुलाई 2009 को पुलिस ने याचिकाकर्ता के घर पर छापा मारा

और उसे एक सह-अभियुक्त के साथ गिरफ्तार कर लिया जिसे बाद में बरी कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने इकबालिया बयान दिए जिनके आधार पर तीन

मोबाइल फोन सेट, जिनमें से दो में सिम कार्ड थे, बरामद किए गए।

द सुंदर @सुंदरराजन बनाम। पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई]

याचिकाकर्ता ने मृतक का गला घोटने, उसके शव को एक बोरे में डालने और उसे मीरांकुलम टैंक में फेंकने की बात कबूल की। मृतक का शव इकबालिया बयान के आधार पर टैंक से बरामद किया गया था

बयान।

12. जाँच के आधार पर याचिकाकर्ता पर आरोप लगाया गया था

भारतीय दंड संहिता की धारा 364 ए, 302 और 201 के तहत। 3 मुकदमा 30 जुलाई 2010 को सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को सौंपा गया था। सत्र न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को उन अपराधों के लिए दोषी ठहराया जिनके लिए उस पर आरोप लगाया गया था और उसे (i) आई. पी. सी. की धारा 364 ए के तहत अपराध के लिए Rs.1000 के जुर्माने के साथ मौत, (ii) आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए Rs.1000 के जुर्माने के साथ मौत; और (ii) सात साल के कठोर कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। 1000 आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत अपराध के लिए। सह-अभियुक्त को सभी अपराधों से बरी कर दिया गया। 13. याचिकाकर्ता की अपील को मद्रास के उच्च न्यायालय ने 30 सितंबर 2010 के एक फैसले से खारिज कर दिया था। द.

उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और मृत्युदंड दोनों की पुष्टि की वाक्य।

14. इस अदालत ने याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया और 5 फरवरी 2013 को मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि की। दोनों ने

उच्च न्यायालय और इस न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि करने से पहले तथ्यों की विस्तृत समीक्षा की।

ग. समीक्षा क्षेत्राधिकार का दायरा

15. संविधान के अनुच्छेद 137 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी फैसले की समीक्षा करने की शक्ति है -

संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधान या अनुच्छेद 145 के तहत कोई नियम। उच्चतम न्यायालय के नियम 2013 को संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत तैयार किया गया है। 2013 के नियमों के आदेश XLVII नियम में यह प्रावधान है कि न्यायालय अपने स्वयं के निर्णय 16 या आदेश की समीक्षा कर सकता है, लेकिन समीक्षा के लिए किसी भी आवेदन पर दीवानी कार्यवाही में विचार नहीं किया जाएगा, सिवाय आधार के।

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश XLVII नियम 1 में उल्लिखित, और अभिलेख के सामने एक स्पष्ट त्रुटि के आधार को छोड़कर एक आपराधिक कार्यवाही में।

17. मोफिल खान बनाम झारखंड राज्य के मामले में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने समीक्षा की शक्ति के दायरे पर चर्चा करते हुए कहा कि:

3 " आई. पी. सी "

" 2013 नियम "

5 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1136 [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. [.....] पुनरीक्षण अपील की पुनः सुनवाई नहीं है और पुनरीक्षण याचिका को बनाए रखने के लिए, यह दिखाना होगा कि न्याय की विफलता हुई है (देखें-सुथेंद्रराज बनाम. राज्य)। एक त्रुटि जो स्वयं स्पष्ट नहीं है और जिसका पता एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जाना है तर्क को शायद ही चेहरे पर स्पष्ट त्रुटि कहा जा सकता है

भले ही आवेदक यह स्थापित करने में सफल हो कि हो सकता है अभियुक्त की दोषसिद्धि या सजा पर एक और संभावित दृष्टिकोण

यह समीक्षा के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। यह न्यायालय अभ्यास करेगा

इसकी समीक्षा करने का अधिकार क्षेत्र केवल तभी है जब कोई स्पष्ट चूक या पेटेंट हो

न्यायिक त्रुटि के कारण पहले के निर्णय में गलती हो गई है। रिकॉर्ड के सामने एक स्पष्ट त्रुटि होनी चाहिए जिससे न्याय की विफलता हो।

डी. अभिलेख के सामने स्पष्ट त्रुटि? डी. 1 वकील की प्रस्तुतियाँ

18. हमने याचिकाकर्ता और राज्य के वकील को सुना है

मिल नाडु। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि

पंखों की त्रुटियाँ रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट हैं और एक के लिए कॉल करते हैं

अपील को खारिज करने वाले फैसले के बारे में:

इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि फोन नंबर जिसके माध्यम से

ए।

फिरौती कॉल कथित रूप से याचिकाकर्ता द्वारा किए गए थे अर्थात XXX5961 के साथ समाप्त होने वाला नंबर याचिकाकर्ता का है; कि कॉल विवरण रिकॉर्ड से पता चलता है कि उपरोक्त-उल्लिखित

बी।

नंबर अलाथुर, पलक्कड़ में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ पंजीकृत है जिसका याचिकाकर्ता से कोई संबंध नहीं है

के साथ;

कि सेल फोन के लिए 15 अंकों का IMEI नंबर, कथित तौर पर

सी.

याचिकाकर्ता से संबंधित जिसमें मोबाइल के साथ सिम है जब्ती ज्ञापन में उल्लिखित संख्या XXX5961 के साथ समाप्त होती है, जो कॉल में उल्लिखित IMEI संख्या से भिन्न होती है

विस्तृत अभिलेख;

इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जिस संख्या पर फिरौती दी गई थी

डी।

कथित तौर पर पीडब्लू1 (मृतक की मां) को फोन किया गया था। अर्थात् XXX847 के साथ समाप्त होने वाली संख्या, PW1 से संबंधित है; सुंदर @सुंदरराजन V.

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई]

पीडब्लू1 ने यह नहीं बताया है कि 28 जुलाई को उन्हें फोन किए गए थे

ई.

2009 और जिस फोन बूथ के माध्यम से कॉल किया गया था, उसके संचालक पीडब्लू 16 की गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

पर; और

भारतीय साक्ष्य की धारा 65 बी के तहत प्रमाण पत्र

एफ.

कॉल विवरण रिकॉर्ड के लिए अधिनियम 18726 प्रस्तुत नहीं किया गया था।

19. तमिलनाडु राज्य के वकील ने याचिकाकर्ता द्वारा आग्रह की गई दलीलों का कड़ा विरोध किया। वकील ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त आधार अभिलेख के सामने स्पष्ट त्रुटियों के बराबर नहीं हैं और परीक्षण न्यायालय, उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों के सामने समीक्षा अधिकार क्षेत्र में इस न्यायालय द्वारा साक्ष्य की पुनः सराहना करने के मानक को पूरा नहीं करते हैं। याचिकाकर्ता द्वारा गुण-दोष पर उठाए गए आधारों का प्रतिवाद करने के लिए वकील ने हमें अभियोजन पक्ष के गवाहों के प्रासंगिक प्रदर्शनों और बयानों के माध्यम से भी लिया।

डी. 2. विश्लेषण

20. हम तमिलनाडु राज्य के वकील से सहमत हैं। याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधारों पर पहले ही अदालतों द्वारा विचार किया जा चुका है जो याचिकाकर्ता के अपराध को दर्ज करने वाले समवर्ती निष्कर्षों पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष का मामला केवल फिरौती के कथित आह्वान पर आधारित नहीं है, बल्कि सुसंगत परस्पर जुड़े साक्ष्य पर आधारित है जैसा कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने अपने निर्णयों में पाया है।

21. इसके बावजूद, हम इससे निपटना उचित समझते हैं

याचिकाकर्ता की दलीलें।

22. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि जिस नंबर के माध्यम से कथित रूप से फिरौती की कॉल की गई थी, वह उसका नहीं था। हालाँकि, 30 जुलाई 2009 के उनके बयान के आधार पर, याचिकाकर्ता से 2 अन्य सेल फोन, मोटरबाइक जिस पर उसने पीड़ित का अपहरण किया था, के साथ-साथ पीड़ित के स्कूल बैग के साथ-साथ XXX5961 के साथ समाप्त होने वाले मोबाइल नंबर के लिए सिम वाला सेल फोन जब्त कर लिया गया था।

निम्नलिखित कारणों से अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित नहीं करता है। जब्ती ज्ञापन और कॉल विवरण में दर्ज आई. एम. ई. आई. संख्या में अंतर

आई. ई. ए. "[2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रिकॉर्ड 15 अंकों की आई. एम. ई. आई. संख्या के अंतिम अंक से संबंधित है। प्रत्येक उपकरण में एक विशिष्ट आई. एम. ई. आई. संख्या होती है जो मॉडल में ब्रांड के मालिक की पहचान करती है। पहले 8 अंक प्रकार आवंटन कोड (टीएसी) अंक हैं जिनमें से प्रारंभिक 2 अंक रिपोर्टिंग निकाय की पहचान करते हैं और अगले 6 अंक रिपोर्टिंग निकाय द्वारा आवंटित ब्रांड मालिक और उपकरण मॉडल की पहचान करते हैं। अगले 6 अंक निर्माता द्वारा अलग-अलग उपकरणों को सौंपे गए अद्वितीय क्रम संख्या हैं। 7

24. याचिकाकर्ता के मामले में ये 14 अंक जब्ती ज्ञापन और कॉल विवरण रिकॉर्ड दोनों में मेल खाते हैं। आई. एम. ई. आई. संख्या में अंतिम अंक है -

' एक एल्गोरिथ्म का उपयोग करके अन्य अंकों के कार्य के आधार पर 'लुह्न चेक डिजिट'। तकनीकी रूप से, अंतिम अंक, जो एकमात्र अंक है जो जब्ती ज्ञापन और कॉल विवरण रिकॉर्ड में अलग है, की गणना एल्गोरिथ्म के माध्यम से पहले 14 अंकों के आधार पर की जा सकती है जो दोनों दस्तावेजों में समान हैं। चूंकि एक आई. एम. ई. आई. संख्या का अंतिम अंक पहले 14 अंकों का एक कार्य है, जब तक कि पहले 14 अंक एक मिलान हैं, यह केवल एक अद्वितीय उपकरण की ओर ले जा सकता है। तदनुसार, यह निष्पत्ति रूप से कहा जा सकता है कि केवल आई. एम. ई. आई. संख्या के अंतिम अंक में अंतर का मतलब यह नहीं हो सकता है कि यह एक अलग उपकरण की आई. एम. ई. आई. संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए,

आई. एम. ई. आई. संख्या के अंतिम अंक में अंतर को उचित रूप से एक टाइपोग्राफिक त्रुटि माना जा सकता है और यह अभियोजन पक्ष के मामले में संदेह पैदा नहीं करता है।

मामला।

25. पीडब्लू1 की संख्या के गैर-सत्यापन के बारे में तर्क, बाद में प्राप्त कॉल के संबंध में पीडब्लू1 के साथ गैर-पुष्टि

पीडब्लू 16 द्वारा दावा किए गए दिन को देर से उठाया गया है।

26. पीडब्लू8 ने अपनी गवाही में कहा है कि याचिकाकर्ता ने उसे पीडब्लू1 के फोन नंबर के बारे में पूछताछ करने के लिए फोन किया और उसने उसे फोन काट लेने के लिए कहा।

फोन करें और फिर से कॉल करें ताकि वह नंबर प्राप्त कर सके और वही प्रदान कर सके, जैसा उसने दूसरी कॉल पर किया था। पीडब्लू1 ने यह भी गवाही दी है कि उसे लगभग 9 बजे फिरौती के लिए कॉल आया था: 30 पीएम। यह याचिकाकर्ता पर था कि वह पीडब्लू1 की प्रतिपरीक्षा के चरण में उसकी संबंधित संख्या XXX847 के साथ समाप्त होने वाले नंबर के बारे में या पीडब्लू16 द्वारा उल्लिखित 28 जुलाई 2009 को याचिकाकर्ता द्वारा कथित रूप से किए गए कॉल के बारे में सवाल उठाए।

27. अंत में, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि धारा 65 बी प्रमाण पत्र के उत्पादन की कमी के कारण सीडीआर पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। 1 उपकरण ब्रांड मालिकों और निर्माताओं के लिए

जी. एस. एम. ए. टी. ए. सी. आवंटन और आई. एम. ई. आई. प्रोग्रामिंग नियम, प्रशिक्षण मार्गदर्शिका
(फरवरी 2018 v1.0)।

सुंदर @सुंदरराजन बनाम। पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई]

कॉल विवरण रिकॉर्ड को कानूनी अधिकारी की गवाही में सत्यापित किया गया था

वोडाफोन, पीडब्लू11, जिन्होंने स्वयं कंप्यूटर से दस्तावेज़ तैयार किए। उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा में विशेष रूप से पुष्टि की है कि याचिकाकर्ता और पीडब्लू1 और पीडब्लू8 के बीच किए गए कॉल का विवरण (जिनसे याचिकाकर्ता द्वारा कॉल के दौरान इसके बारे में पूछताछ करने के बाद पीडब्लू1 का नंबर प्राप्त हुआ था)। XXX5961 पर समाप्त होने वाले मोबाइल नंबर के कॉल विवरण रिकॉर्ड इस बात की पुष्टि करते हैं कि PW8 पर दो कॉल किए गए थे।

9: 22 पीएम और 9: 25 27 जुलाई 2009 को प्रधानमंत्री। इसके तुरंत बाद उन्होंने 9 बजे XXX847 के साथ समाप्त होने वाले नंबर पर कॉल किया: 39 पीएम। हालाँकि, यह स्वीकार किया जाता है कि आई. ई. ए. की धारा 65 बी के तहत उल्लिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। 28. आई. ई. ए. में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 20008 द्वारा विभिन्न अन्य संशोधनों के साथ धारा 65 बी को जोड़ा गया था।

लेखा डिजिटल साक्ष्य। धारा 65 बी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की स्वीकार्यता का प्रावधान करती है।

29. आई. ई. ए. की धारा 65 बी नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:
" 65 - बी. इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की स्वीकार्यता। - (1)

कंप्यूटर द्वारा उत्पादित ऑप्टिकल या चुंबकीय माध्यम में संग्रहीत, रिकॉर्ड या प्रतिलिपि (इसके बाद "कंप्यूटर आउटपुट" के रूप में संदर्भित) को भी एक दस्तावेज माना जाएगा, यदि इस धारा में उल्लिखित शर्तें जानकारी के संबंध में संतुष्ट हैं और विचाराधीन कंप्यूटर और मूल के किसी भी सामग्री या उसमें बताए गए किसी भी तथ्य के साक्ष्य के रूप में, मूल के आगे के प्रमाण या उत्पादन के बिना, किसी भी कार्यवाही में स्वीकार्य होगा।

प्रत्यक्ष साक्ष्य स्वीकार्य होगा।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट शर्तें
कंप्यूटर आउटपुट निम्नलिखित होगा, अर्थात्

(क) सूचना युक्त कंप्यूटर आउटपुट उस अवधि के दौरान कंप्यूटर द्वारा उत्पादित किया गया था जब कंप्यूटर का उपयोग कंप्यूटर के उपयोग पर वैध नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस अवधि में नियमित रूप से की जाने वाली किसी भी गतिविधि के उद्देश्यों के लिए जानकारी को संग्रहीत करने या संसाधित करने के लिए कंप्यूटर का नियमित रूप से उपयोग किया जाता था।

(ख) उक्त अवधि के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित या उस प्रकार की जानकारी जिससे जानकारी इस प्रकार है।

अधिनियम "[2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निहित व्युत्पन्न को उक्त गतिविधियों के सामान्य पाठ्यक्रम में नियमित रूप से कंप्यूटर में डाला जाता था;

ग) उक्त अवधि के पूरे भौतिक भाग में, कंप्यूटर ठीक से काम कर रहा था या, यदि नहीं, तो किसी भी अवधि के संबंध में जिसमें यह ठीक से काम नहीं कर रहा था या अवधि के उस हिस्से के दौरान काम नहीं कर रहा था, ऐसा नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इसकी सामग्री की सटीकता को प्रभावित करे; और

(घ) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित जानकारी उक्त गतिविधियों के सामान्य क्रम में कंप्यूटर में दी गई ऐसी जानकारी को पुनः प्रस्तुत करती है या उससे प्राप्त होती है।

(3) जहाँ किसी भी अवधि में, किसी भी गतिविधि के उद्देश्यों के लिए जानकारी को संग्रहीत करने या संसाधित करने का कार्य नियमित रूप से किया जाता है।

उस अवधि में जैसा कि उप-धारा (2) के खंड (ए) में उल्लेख किया गया है, कंप्यूटर द्वारा नियमित रूप से किया जाता था, चाहे

(क) उस अवधि में काम करने वाले कंप्यूटरों के संयोजन द्वारा; या

(ख) उस अवधि में लगातार काम करने वाले विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा;

या

(बी) उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के उत्पादन में शामिल किसी भी उपकरण का ऐसा विवरण देना जो यह दिखाने के उद्देश्य से उचित हो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एक कंप्यूटर द्वारा बनाया गया था; (ग) उप-धारा (2) में उल्लिखित शर्तों से संबंधित किसी भी मामले से निपटने के लिए, सुंदर @सुंदरराजन V.

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई]

और संबंधित उपकरण के संचालन या संबंधित गतिविधियों के प्रबंधन (जो भी उचित हो) के संबंध में एक जिम्मेदार आधिकारिक पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना प्रमाण पत्र में बताए गए किसी भी मामले का प्रमाण होगा और इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए यह होगा -

किसी मामले को सर्वोत्तम ज्ञान के साथ कहने के लिए पर्याप्त है।

और इसे बताने वाले व्यक्ति का विश्वास।

(ख) क्या किसी अधिकारी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के दौरान, जानकारी को संग्रहीत या संसाधित किए जाने की दृष्टि से प्रदान किया जाता है। उन गतिविधियों के उद्देश्यों के लिए एक कंप्यूटर द्वारा संचालित

मानव हस्तक्षेप) किसी भी उपयुक्त उपकरण के माध्यम से। स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजनों के लिए अन्य जानकारी से प्राप्त की जा रही जानकारी का कोई भी संदर्भ गणना, तुलना द्वारा उससे प्राप्त होने का संदर्भ होगा।

या कोई अन्य प्रक्रिया।

30. याचिकाकर्ता ने अर्जुन पंडितराव खोटकर बनाम कैलाश कुषाणराव गोरंठ्याल मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया है। अनवर पी. वी. बनाम पी. पी. के. बशीर 10 में आई. ई. ए. की धारा 65 बी के साथ अनिवार्य अनुपालन की आवश्यकता वाले निर्णय में उक्ति को दोहराया गया।

31. इस प्रावधान पर सबसे शुरुआती फैसलों में से एक राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम नवजोत संधू की इस अदालत की दो न्यायाधीशों की पीठ का था।

जहाँ न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 65 बी केवल प्रावधानों में से एक थी

जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के माध्यम से द्वितीयक साक्ष्य हो सकता है 9 9 2020 (7)
एससीसी 1

10 10 2014 (10) एस. सी. सी 473 11 2005 (11) एससीसी 600 [2023]
5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और यह कि अन्य मान्यताओं के माध्यम से साक्ष्य को स्वीकार करने पर कोई रोक नहीं थी। न्यायालय ने कहा कि:

150. धारा 63 के अनुसार, "द्वितीयक साक्ष्य" का अर्थ है और

चलने योग्य। यह विवाद में नहीं है कि इसमें निहित जानकारी कॉल रिकॉर्ड विशाल सर्वरों में संग्रहीत किए जाते हैं जिन्हें आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

और अदालत में पेश किया गया। उच्च न्यायालय ने भी यही कहा है

पैरा 276 में देखा गया। इसलिए, कंप्यूटर से लिए गए प्रिंटआउट /

यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा सर्वर और एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा प्रमाणित

कानून अनुमति देने पर भी द्वितीयक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है। उल्लिखित परिस्थितियों में दिए जाने वाले ऐसे साक्ष्य

संबंधित प्रावधानों, अर्थात् धारा 63 और 65 में।

(जोर दिया गया)

32. नवजोत संधू में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, वह था

अनवर पी. वी. मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया।

मान लिया कि:

22. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित साक्ष्य, जैसा कि उल्लेख किया गया है इससे पहले, एक विशेष प्रावधान होने के नाते, सामान्य कानून

धारा 65 के साथ पठित धारा 63 के तहत द्वितीयक साक्ष्य

साक्ष्य अधिनियम से भी ऐसा ही होगा। जनरलिया स्पेशलिबस नॉन

अपमानजनक, विशेष कानून हमेशा सामान्य कानून पर हावी रहेगा। यह.

ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय ने धारा 59 और 65-ए पर ध्यान देना छोड़ दिया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की स्वीकार्यता से संबंधित।

धारा 63 सुंदर @सुंदरराजन बनाम। पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के माध्यम से; वही पूरी तरह से नियंत्रित है धारा 65-ए और 65-बी द्वारा। इस हद तक, बयान

संबंधित द्वितीयक साक्ष्य की ग्राह्यता पर कानून इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जैसा कि इस अदालत ने नवजोत संधू में कहा है

द्वितीयक साक्ष्य के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक धारा 65-बी के तहत आवश्यकताएं नहीं हैं

संतुष्ट। इस प्रकार सी. डी., बी. सी. डी., चिप आदि के मामले में भी ऐसा ही है। धारा 65-बी के संदर्भ में प्रमाण पत्र के साथ होगा

दस्तावेज़ लेते समय प्राप्त किया गया, जिसके बिना,

उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित द्वितीयक साक्ष्य है -

अस्वीकार्य।

(जोर दिया गया)

33. तदनुसार, अनवर पी. बी. में स्वीकार करने के लिए निर्णय के संदर्भ में

द्वितीयक साक्ष्य के माध्यम से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, जैसे कि सी. डी. आर., धारा 65 बी की आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता होगी और ऐसे साक्ष्य के प्रवेश के लिए आई. ई. ए. के तहत कोई अन्य मार्ग नहीं अपनाया जा सकता है।

34. हालांकि, टोमासो ब्रूनो बनाम स्टेट ऑफ

उत्तर प्रदेश 1 2 ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया और कहा कि अनवर पी. बी. में निर्णय का उल्लेख किए बिना साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के तहत एक दस्तावेज़ की सामग्री के द्वितीयक साक्ष्य का भी नेतृत्व किया जा सकता है।

24. सूचना प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ, वैज्ञानिक

व्यक्ति में और संस्थागत स्तर पर गुस्सा व्याप्त होना चाहिए।

जाँच के तरीके। बढ़ते प्रभाव के साथ

रोजमर्रा की जिंदगी में प्रौद्योगिकी और इसके परिणामस्वरूप, उत्पादन

मामलों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य स्थापित करने के लिए प्रासंगिक हो गया है

अभियुक्त का अपराध या प्रतिवादी का दायित्व। इलेक्ट्रॉनिक

दस्तावेजों को भौतिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। के साथ

2000 में साक्ष्य अधिनियम में संशोधन, धारा 65-ए और

65 - बी को वृत्तचित्र से संबंधित अध्याय V में पेश किया गया था।

सबूत। धारा 65-ए में प्रावधान है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री

साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है यदि धारा में दिए गए मानदंड

12 2015 (7) एससीसी 178 [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

65 - बी का अनुपालन किया जाता है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उत्पन्न करता है

धारा 65-बी दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार्य बनाती है, कागज का प्रिंटआउट उत्पादित ऑप्टिकल या चुंबकीय मीडिया में संग्रहीत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड

एक कंप्यूटर द्वारा, निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति के अधीन धारा 65-ख की उप-धारा (2) में। द्वितीयक साक्ष्य

दस्तावेज़ की सामग्री को धारा 65 के तहत भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

साक्ष्य अधिनियम। पीडब्लू 13 ने कहा कि उन्होंने पूरा वीडियो देखा

सीसीटीवी कैमरे में दुर्भाग्यपूर्ण रात की रिकॉर्डिंग, लेकिन उसने नहीं की है

केस डायरी में दर्ज किया गया है कि कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है

सबूत के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

(जोर दिया गया)

35. शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल राज्य मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ

इश 1 3 13 अनवर पी. बी. से और भी दूर भटक गया और माना कि

ओएनएस 65 ए और 65 बी को सीटी पर एक पूर्ण कोड नहीं माना जा सकता है। इसमें कहा गया था कि:

अनवर पी. बी. बनाम. पी. के. बशीर, तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया। पैरा 24 में उक्त निर्णय में यह देखा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक

प्राथमिक साक्ष्य के रूप में साक्ष्य धारा 62 द्वारा कवर किया गया था।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी की किस प्रक्रिया के लिए

साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी की प्रक्रिया थी इसका पालन करने की आवश्यकता है और नवजोत में एक विपरीत दृष्टिकोण लिया गया है

संभू ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का द्वितीयक साक्ष्य हो सकता है

साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 और 65 के तहत कवर नहीं किया गया था

सही है। हालाँकि, पैरा 14 में प्रभाव के लिए अवलोकन हैं।

कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड केवल धारा 65-बी के अनुसार साबित किया जा सकता है साक्ष्य अधिनियम।

25. हालांकि टोमासो में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसलों को देखते हुए

साक्ष्य स्वीकार्य है और धारा 65 के तहत प्रावधान हैं।
स्पष्टीकरण के रूप में हैं।

साक्ष्य अधिनियम के ए और 65-बी

और प्रक्रियात्मक प्रावधान हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक सबूत

प्रामाणिक और प्रासंगिक है जिसे निश्चित रूप से स्वीकार किया जा सकता है

बी (2) एस. सी. सी. 801 एन. डी. ए. आर. @सुंदरराजन बनाम। पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई]

इसकी प्रामाणिकता के बारे में अदालत के संतुष्ट होने के अधीन

और इसकी स्वीकार्यता की प्रक्रिया तथ्य पर निर्भर हो सकती है।

साक्ष्य धारा के तहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में है 65 - बी (4)।

26. साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65-ए और 65-बी लागू नहीं हो सकती है।

विषय पर एक पूर्ण कोड माना जाए। अनवर पी. बी. में

इस न्यायालय ने पैरा 24 में स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रॉनिक का प्राथमिक साक्ष्य

अभिलेख धारा 65-ए और 65-बी के तहत शामिल नहीं था

साक्ष्य अधिनियम। प्राथमिक साक्ष्य वह दस्तावेज़ है जो पहले प्रस्तुत किया गया था।

अदालत और अभिव्यक्ति "दस्तावेज़" को धारा 3 में परिभाषित किया गया है।

साक्ष्य अधिनियम का अर्थ व्यक्त या वर्णित कोई भी मामला है। किसी भी पदार्थ पर अक्षरों, आकृतियों या निशानों के माध्यम से, या

उन साधनों में से एक से अधिक, जिनका उपयोग करने का इरादा है, या जो

उपयोग किया जाए, उस मामले को दर्ज करने के उद्देश्य से।

(जोर दिया गया)

36. शफी मोहम्मद के मामले में अदालत ने आवश्यकता को भी कम कर दिया

धारा 65 बी प्रमाणपत्र। इससे इनमें विरोधाभासी स्थितियाँ पैदा हुईं।

अनवर पी. बी. द्वारा निर्धारित कानून, जिसका निपटारा एक

अर्जुन पंडितराव मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठकार। अदालत ने अनवर पी. बी. को दोहराया और टोमासो ब्रूनो को प्रति

इयाम और शफी मोहम्मद पर शासन किया। इसमें कहा गया था कि:

73. इस प्रकार संदर्भ का उत्तर यह कहते हुए दिया जाता है कि:

73.1 . अनवर पी. बी., जैसा कि हमने ऊपर स्पष्ट किया है, कानून है।

इस न्यायालय द्वारा साक्ष्य की धारा 65-बी पर घोषित किया गया

एक्ट करें। टोमासो ब्रूनो में निर्णय, इनक्यूरियम के अनुसार,

कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं करता है। साथ ही, फैसला

शफी मोहम्मद में और 3-4-2018 दिनांकित निर्णय

शफी मोहम्मद के रूप में रिपोर्ट किया गया। वी. एच. पी. राज्य, नीचे न रखें

कानून सही है और इसलिए खारिज कर दिया जाता है।

73.2 . ऊपर उल्लिखित स्पष्टीकरण यह है कि आवश्यक

धारा 65-बी (4) के तहत प्रमाण पत्र अनावश्यक है यदि मूल

लैपटॉप कंप्यूटर, कंप्यूटर टैबलेट या यहां तक कि एक मोबाइल फोन, गवाह बॉक्स में कदम रखते हुए और यह साबित करते हुए कि उपकरण संबंधित है,

जिस पर मूल जानकारी पहले संग्रहीत की जाती है, स्वामित्व में है और/या उसके द्वारा संचालित। ऐसे मामलों में जहां "कंप्यूटर" [2023] 5 एस. सी. आर. के साथ होता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"कंप्यूटर सिस्टम" या "कंप्यूटर नेटवर्क" का हिस्सा बनें और भौतिक रूप से ऐसी प्रणाली लाना असंभव हो जाता है

या अदालत के लिए नेटवर्क, तो प्रदान करने का एकमात्र साधन

इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित जानकारी में हो सकता है

धारा 65-बी (1) के अनुसार, आवश्यकता के साथ

धारा 65-बी (4) के तहत प्रमाण पत्र। पैरा में अंतिम वाक्य

24 अनवर पी. वी. में जो इस प्रकार है "। यदि एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में इसका उपयोग धारा 62 के तहत प्राथमिक साक्ष्य के रूप में किया जाता है।

साक्ष्य अधिनियम "। इस प्रकार स्पष्ट किया गया है; इसे बिना पढ़े पढ़ा जाना चाहिए।

शब्द "साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 के तहत",। इसके साथ

स्पष्टीकरण, अनवर पी. वी. के पैरा 24 में वर्णित कानून की आवश्यकता नहीं है

पुनरीक्षण करने के लिए।

(जोर दिया गया)

37. इसलिए, अब कानून तय हो गया है: धारा 65 बी प्रमाणपत्र है

अनवर पी. वी. में इस न्यायालय के फैसले के संदर्भ में अनिवार्य है जैसा कि अर्जुन पंडितराव खोटकर में पुष्टि की गई है।

38. हालाँकि, अनवर पी. वी. का फैसला 18 सितंबर 2014 को किया गया था। तब तक

फिर, नवजोत संधू में कानून की व्याख्या, जो 4 अगस्त 2005 को तय की गई थी, प्रबल हो गई। तत्काल मामले में, निचली अदालत ने 30 जुलाई 2010 को अपना फैसला सुनाया। दो महीने बाद, 30 सितंबर 2010 को, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के मौत की सजा देने के फैसले की पुष्टि की। इस अदालत ने अपील को खारिज कर दिया और 5 फरवरी 2013 को मौत की सजा की पुष्टि की। यहां तक कि समीक्षा याचिका को 20 मार्च 2013 को चैंबरों में खारिज कर दिया गया था, जिसे मोहम्मद में संविधान पीठ के फैसले को देखते हुए तत्काल कार्यवाही में फिर से खोला गया था। आरिफ उर्फ अशफाक।

39. तदनुसार, किसी भी अदालत को निर्धारित कानून का लाभ नहीं मिला

अनवर पी. वी. में धारा 65 बी प्रमाणपत्र की अनिवार्य आवश्यकता के तहत अदालतों के साथ-साथ जांच एजेंसी उस समय प्रचलित कानून के अनुसार आगे बढ़ी।

40. सोनू उर्फ अमर बनाम हरियाणा राज्य 1 4 में यह अदालत

अनवर पी. वी. के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग के उन परीक्षणों पर प्रभाव पर विचार किया जो पहले से ही उस अवधि के दौरान आयोजित किए जा चुके थे जब नवजोत संधू ने मैदान पर कब्जा कर लिया था और कहा था कि:

37. इस न्यायालय द्वारा धारा 65-बी (4) की व्याख्या

नवजोत संधू में दिनांकित 4-8-2005 के फैसले ने तब तक मैदान को संभाला

14 1 4 2017 (8) एस. सी. सी. 570 सुंदर @सुंदरराजन बनाम।

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई]

अनवर मामले में 18-9-2014 पर खारिज कर दिया गया था। इस देश की सभी आपराधिक अदालतें इस अदालत द्वारा व्याख्या किए गए कानून का पालन करने के लिए बाध्य हैं। नवजोत संधू में धारा 65-बी की व्याख्या के कारण, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साबित करने के लिए प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं थी। 4-8-2005 और 18-9-2014 के बीच की अवधि के दौरान बड़ी संख्या में परीक्षण किए गए हैं। प्रमाण पत्र के बिना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य में जोड़ा जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनवर मामले में इस न्यायालय के फैसले को तब तक पूर्वव्यापी होना चाहिए जब तक कि "संभावित ओवररूलिंग" का न्यायिक उपकरण लागू नहीं किया जाता है। हालाँकि, निर्णय का पूर्वव्यापी अनुप्रयोग न्याय प्रशासन के हित में नहीं है क्योंकि इसके लिए बड़ी संख्या में आपराधिक मामलों को फिर से खोलने की आवश्यकता होगी। बिना प्रमाणन के साक्ष्य में प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के आधार पर निर्णय लिए गए आपराधिक मामलों को अपीलीय स्तर पर जब भी अभियुक्त द्वारा आपत्तियां ली जाती हैं, तो उन पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। जिन मामलों को फिर से खोलने का प्रयास किया जाएगा

अंतिम।

41. हालांकि, इसने इस मुद्दे को दो न्यायाधीशों की पीठ होने के नाते तय नहीं किया और कानून के सवाल को इस मामले में फैसला करने के लिए खुला रखा।

उपयुक्त मामला। अर्जुन पंडितराव खोटकर में इस अदालत ने सोनू में उठाए गए सवाल पर विचार नहीं किया।

42. दूसरी ओर, सोनू ने इस सवाल से निपटा कि क्या, अपीलीय स्तर पर, सीडीआर पर निर्भरता पर पुनर्विचार किया जा सकता है यदि

मुकदमे के दौरान आपत्ति नहीं उठाई गई थी। जैसा कि तमिलनाडु राज्य के वकील ने तर्क दिया है, बचाव पक्ष ने भी मुकदमे में या अपीलीय स्तर पर धारा 65 बी प्रमाणपत्र के अभाव में सीडीआर के अस्वीकार्य होने की याचिका नहीं उठाई। इस मुद्दे पर, इस अदालत ने सोनू में नोट किया कि:

32. यह किसी का मामला नहीं है कि सी. डी. आर. जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का एक रूप हैं, साक्ष्य में स्वाभाविक रूप से स्वीकार्य नहीं हैं। आपत्ति यह है कि उन्हें निचली अदालत के समक्ष धारा 65-बी (4) द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र के बिना चिह्नित किया गया था। ऊपर उल्लिखित निर्णयों से यह स्पष्ट है कि प्रमाण के तरीके या विधि से संबंधित आपत्ति दस्तावेज़ को एक प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित करते समय उठाई जानी चाहिए, न कि बाद में। महत्वपूर्ण परीक्षण, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, यह है कि क्या दस्तावेज़ को चिह्नित करने के चरण में दोष को ठीक किया जा सकता था। वर्तमान मामले में इस परीक्षण को लागू करना, यदि सी. डी. आर. को [2023] 5 एस. सी. आर. के बिना चिह्नित किए जाने पर कोई आपत्ति ली गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रमाण पत्र, न्यायालय अभियोजन पक्ष को दे सकता था

कमी को दूर करने का अवसर। यह ऊपर से भी स्पष्ट है।

निर्णय जो दस्तावेजों की स्वीकार्यता के संबंध में आपत्तियाँ करते हैं

जो स्वयं अस्वीकार्य हैं, उन्हें अपीलीय न्यायालय में भी लिया जा सकता है।

स्टेज। एक दस्तावेज की स्वीकार्यता जो स्वाभाविक रूप से अस्वीकार्य है

यह एक बुनियादी मुद्दा है। प्रमाण का तरीका या तरीका है प्रक्रियात्मक और आपत्तियाँ, यदि मुकदमे में नहीं ली जाती हैं, तो

अपीलीय चरण में अनुमति दी जाए। यदि आपत्तियाँ

अपील में प्रमाण लेने की अनुमति है

एक पक्ष द्वारा मंच, दूसरे पक्ष के पास अवसर नहीं है

कमियों को दूर करना। के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील

राज्य ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के तहत बयानों का उल्लेख किया है।

उक्त श्रेणी के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों के एक उदाहरण के रूप में स्वाभाविक रूप से अस्वीकार्य साक्ष्य। सी. डी. आर. उक्त में नहीं आते हैं

दस्तावेजों की श्रेणी। हम संतुष्ट हैं कि एक आपत्ति है कि सी. डी. आर. प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण अविश्वसनीय हैं

धारा 65-बी (4) में विहित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है

इस स्तर पर उठाया गया क्योंकि आपत्ति मोड से संबंधित है या

प्रमाण की विधि।

(जोर दिया गया)

43. जबकि अर्जुन पंडितराव खोटकर के मामले में अदालत ने प्रत्यक्ष रूप से ऐसा नहीं किया

धारा 65 बी के तहत प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण सी. डी. आर. के खिलाफ आपत्तियों की अनुमति देने के मुद्दे को विलंबित स्तर पर उठाया जा रहा है।

अभियोजन की अनुमति देने के लिए, असाधारण मामलों में, परीक्षण अदालतों के लिए खुला है

बाद के चरण में इस तरह के प्रमाण पत्र का परीक्षण करें। इसमें कहा गया था कि:

54. इसलिए, सामान्य प्रक्रिया के संदर्भ में, अभियोजन है

उन सभी दस्तावेजों की आपूर्ति करने के लिए बाध्य है जिन पर निर्भरता हो सकती है

मुकदमा शुरू होने से पहले एक अभियुक्त के सामने रखा जाता है। इस प्रकार,

अनुमति देने में आपराधिक मुकदमों में अदालतों द्वारा शक्ति का प्रयोग बाद में दायर किए जाने वाले साक्ष्य का परिणाम गंभीर या गंभीर नहीं होना चाहिए।

अभियुक्त के प्रति अपरिवर्तनीय पूर्वाग्रह। एक संतुलन अभ्यास

पक्षकारों के अधिकारों का सम्मान न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए,

धाराओं के तहत अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी आवेदन की जांच करने में

91 या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 या धारा 165

साक्ष्य अधिनियम। प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर, और न्यायालय यह देखने के बाद विवेक का प्रयोग कर रहा है कि अभियुक्त

निष्पक्ष सुनवाई के अभाव में न्यायालय सुंदर @सुंदरराजन बनाम मामले में पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है।

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई]

उचित मामले अभियोजन पक्ष को इस तरह के मामले पेश करने की अनुमति देते हैं बाद में प्रमाण पत्र। अगर आरोपी कौन है

अपने बचाव के हिस्से के रूप में आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहता है,

यह फिर से मामले के न्याय पर निर्भर करेगा-विवेक

न्यायालय द्वारा कानून के अनुसार प्रयोग किया गया।

(जोर दिया गया)

44. इसलिए, हम सोनू में अनुपात से सहमत होने के लिए इच्छुक हैं

धारा 65 बी प्रमाणपत्र के अभाव में, विशेष रूप से उन मामलों में, जहां मुकदमा 18 सितंबर 2014 से पहले पूरा हो गया है, यानी अनवर पी. वी. में निर्णय की घोषणा से पहले, सी. डी. आर. स्वीकार्य नहीं हैं, जो देर से उठाए गए स्तर पर उठाई गई आपत्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। हालाँकि, हम इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हैं कि तत्काल मामले में मौत की सजा दी गई है।

45. हाल ही में, मोहम्मद में। आरिफ बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) 1, ए

इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मृत्युदंड की समीक्षा से जुड़े एक मामले में समीक्षा याचिका पर निर्णय लेते समय इसी तरह की तथ्य स्थिति का सामना किया, जहां निचली अदालत और अपीलीय अदालतों के फैसले उस अवधि के दौरान दिए गए थे जब नवजोत संधू प्रचलित कानून थे। उस मामले में भी, न्यायालय ने इस बात पर ध्यान दिया कि यह मौत की सजा से जुड़ा मामला है और कहा कि:

" 24. नवजोत संधू को 4.8.2005 यानी इससे पहले तय किया गया था

तत्काल मामले में निचली अदालत द्वारा फैसला सुनाया गया था।

उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के बाद के निर्णय थे

क्रमशः 13.9.2007 और 10.8.2011 पर पारित किया गया

मृत्युदंड का पुरस्कार। ये दोनों निर्णय दिए गए थे।

अनवर पी. वी. में इस न्यायालय के निर्णय से पहले जो दिया गया था

18.9.2014 पर। विचारण न्यायालय, उच्च न्यायालय और

इस प्रकार यह न्यायालय अनवर पी. वी. में निर्णय से काफी पहले था और

अनिवार्य रूप से नवजोत में निर्धारित कानून की पृष्ठभूमि में थे संधू। अगर हम पैराग्राफ 32 में स्वीकार किए गए सिद्धांत के अनुसार चलते हैं

सोनू उर्फ अमर में निर्णय का मामला चल सकता है

एक पूरी तरह से अलग आधार। यही कारण है कि इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर निर्भरता रखी गई है।

जिनसे तब कानून के अनुसार निपटा गया था प्रचलित है। हालाँकि, चूंकि तत्काल मामला संबंधित है

15 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1509 [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मृत्युदंड का अधिनिर्णय, यह समीक्षा याचिका होनी चाहिए

इस न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णयों के आलोक में विचार किया गया

अनवर पी. वी. और अर्जुन पंडितराव।

25. नतीजतन, हमें वर्तमान के लिए बचना चाहिए

उद्देश्यों के लिए, सीडीआर के रूप में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो

धारा 65 के तहत किसी भी उपयुक्त प्रमाण पत्र के बिना था
साक्ष्य अधिनियम का बी (4) "।

(जोर दिया गया)

46. तदनुसार, हम भी इस समीक्षा पर विचार करना उचित समझते हैं।

सी. डी. आर. के रूप में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को छोड़कर याचिका

वे धारा 65 बी के तहत उपयुक्त प्रमाण पत्र के बिना हैं, भले ही कानून, जैसा कि वर्तमान मामले में मुकदमे
के दौरान था, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को स्वीकार करने की अनुमति देता है।

47. तदनुसार, हम उच्च न्यायालय द्वारा विचार किए गए साक्ष्य का विश्लेषण करते हैं।

सी. डी. आर. पर भरोसा किए बिना अपील में न्यायालय और यह न्यायालय। उच्च न्यायालय ने आने से
पहले अपने फैसले में निम्नलिखित साक्ष्यों पर ध्यान दिया याचिकाकर्ता के अपराध के समापन पर
और उसकी दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए:

18. पी. डब्ल्यू. 1 के अनुसार मृतक बच्चे की मां सुरेश,

बच्चा रोज सुबह करीब 8 बजे स्कूल जाता था।

और शाम को लगभग 4:30 बजे वापस आएंगे, और घटना की तारीख को,

अर्थात्, 27.7.2009, बच्चा हमेशा की तरह स्कूल जाता था। इन से

पी. डब्ल्यू. 6, शक्ति मैट्रिक के संवाददाता का साक्ष्य
स्कूल, वृधाचलम, और उपस्थिति रजिस्टर, Ex.P3, यह

यह बिल्कुल स्पष्ट होगा कि बच्चा उस दिन स्कूल गया था

और उसके लिए बनी वैन में स्कूल से लौट रहा था

उद्देश्य। पीडब्लू 2 के अनुसार, वह भी पढ़ाई कर रही है

मृतक सुरेश, और उस दिन, दोनों घर से लौट रहे थे
वैन में स्कूल गया और करकुडल में उतरा, और उस समय ए-1

जो मोटरबाइक के साथ नीम के पेड़ के नीचे खड़ा था, उनके पास आया और बच्चे सुरेश को बताया कि उसकी माँ और दोनों

दादी ठीक नहीं थी और उस झूठे कारण से, ले लिया

उस जगह का बच्चा। पी. डब्ल्यू. 2 के साक्ष्य बहुत थे

अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा टिप्पणी की गई। लेकिन, वे

विवादों पर सहमति नहीं हो सकती है। विद्वत विचारण न्यायाधीश ने

साक्ष्य दर्ज करने से पहले स्पष्ट रूप से इंगित किया गया कि साक्ष्य देने के लिए बच्चे पी. डब्ल्यू. 2 के मस्तिष्क की परिपक्वता थी

वास्तव में परीक्षण किया गया और संतोषजनक पाया गया, और फिर उन्होंने एन. डी. ए. आर.
@एस. एन. डी. ए. आर. ए. आर. ए. आर. ए. आर. ए. आर. ए. आर. ए. आर. ए. आर. ए. आर. ए. आर. ए.
आर. ए. आर. ए. आर. ए. आर. ए. आर. ए. आर. ए. आर. ए. आर. ए. आर. ए. आर. ए. आर. ए. आर. ए. आर.
ए. आर. ए. आर. ए. आर. ए. आर. ए. आर. ए. आर. ए. आर. ए. आर. ए. आर. ए. आर. ए. आर. ए. आर. ए.
आर. ए. आर. ए. आर. ए. आर. ए. आर. ए. आर. ए. आर. ए. आर. ए. आर. ए. आर. ए. आर. ए. आर

निरीक्षक द्वारा कथन

पुलिस [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई]

सबूत। घटना के समय बच्चा 10 साल का था।

और सबूत देने के समय, यह 11 साल का था।

[.....] 19. यह बिल्कुल स्पष्ट होगा कि यदि किसी बाल गवाह का साक्ष्य ठोस और विश्वसनीय है, तो न्यायालय उस साक्ष्य को स्वीकार कर सकता है। में

तत्काल मामले में, पी. डब्ल्यू. 2 का साक्ष्य ऊपर वर्णित है। पीडब्लू. 1 के अनुसार, जब बच्ची शाम 4:30 बजे तक नहीं लौटी, तो तुरंत उसे संदेह हुआ और वह अपने बेटे की तलाश में चली गई, और वह तुरंत दूसरे बच्चे पीडब्लू. 2 से मिली। पी. डब्ल्यू. 2 ने पी. डब्ल्यू. 1 को सूचित किया कि बच्चे सुरेश को मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति उपरोक्त कारण बताते हुए ले गया था। अब, इस मोड़ पर, पी. डब्ल्यू. 2 के साक्ष्य को स्वीकार करने के लिए, न्यायालय की सुविचारित राय में, EX.P1 में पाया गया सबसे पहला संस्करण पर्याप्त होगा। EX.P1, शिकायत के अवलोकन से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि बच्चे के वापस नहीं आने के बाद, पी. डब्ल्यू. 1 दूसरी बच्ची पी. डब्ल्यू. 2 कमाली से मिली, और वह थी

पी. डब्ल्यू. 2 द्वारा सूचित किया गया कि बच्चे को एक व्यक्ति द्वारा ले जाया गया था उपरोक्त झूठे कारणों के साथ मोटरबाइक। इस प्रकार इसमें पाया गया सबसे पहला संस्करण स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि पी. डब्ल्यू. 2 एक सही संस्करण के साथ आया है। इसके अलावा, बच्चा अदालत के समक्ष एम. ओ. 5 के रूप में चिह्नित मोटरबाइक की पहचान करने में सक्षम था। जिरह के बावजूद

पूरी तरह से, पी. डब्ल्यू. 2 बच्चे का साक्ष्य अडिग रहा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में निर्धारित अनुपात के बाद, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि पी. डब्ल्यू. 2 के साक्ष्य को स्वीकार किया जाना चाहिए।

पी. डब्ल्यू. 3. पी. डब्ल्यू. 3 उसी गाँव के मूल निवासी थे और इन सभी व्यक्तियों को वे पहले से ही जानते थे। पी. डब्ल्यू. 3 पर्याप्त रूप से परिपक्व थे और उनकी आयु 41 वर्ष थी। उनके अनुसार, वह वास्तव में रास्ते में आ रहा था, और जब स्कूल बस को रोका गया, तो पी. डब्ल्यू. 2 और मृतक सुरेश उतर गया, और बच्चे को ए-1 द्वारा बुलाया गया, और किसी कारण से, बच्चे को बाइक में ले जाया गया जिसे उसने देखा।

पी. डब्ल्यू. 3 ने भी पहचान परेड में भाग लिया और

ए-1 को ठीक से पहचाना गया। अब, अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा की गई टिप्पणी कि पहचान परेड के संबंध में, दुर्बलताएं देखी गई थीं, को कानून में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

में [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जहां तक यह टिप्पणी की गई है कि जांच अधिकारी द्वारा परीक्षण पहचान परेड के लिए कोई मांग नहीं की गई थी या ए-1 के हस्ताक्षर प्राप्त नहीं किए गए थे, तो इसे इस कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि जहां तक P.W.10 द्वारा आयोजित पहचान परेड का संबंध है, यह केवल जांच अधिकारी द्वारा की गई मांग पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेशों के अनुसार था; अन्यथा, यह बिल्कुल नहीं हो सकता था। ए-1 की पहचान करने के लिए पहचान परेड का संचालन जिसमें P.Ws.2 और 3 ने भाग लिया है, निचली अदालत के समक्ष अपीलार्थी द्वारा कभी भी अस्वीकार नहीं किया गया था। इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि परीक्षण पहचान परेड ठीक से की गई थी, और विचारण न्यायाधीश उस संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को स्वीकार करने में पूरी तरह से सही था।

21. उपरोक्त के अलावा, पहचान परेड के संबंध में कानूनी स्थिति को इंगित करना उचित है। यह तय हो गया है।

कानून का प्रस्ताव है कि पहचान परेड केवल एक है

साक्ष्य का पुष्टिकारक अंश और न्यायालय में की गई पहचान, साक्ष्य का एक ठोस अंश है। अदालत को इस बात पर गौर करना चाहिए कि क्या उस समय जब गवाहों ने आरोपी को मृतक के साथ देखा था, इस तरह की बात के कारण एक उनकी यादों में छेदा। तत्काल मामले में, बच्चा केवल 7 साल का था, और बच्चा और पी. डब्ल्यू. 2 कमली दोनों जो बच्चे के साथ आ रहे थे, एक साथ उतर गए, और अपीलार्थी/ए-1 वहाँ आया और मामूली कारण से बच्चे को ले गया। ऐसी स्थिति में, स्वाभाविक रूप से पी. डब्ल्यू. 2 की स्मृति में कमी आई होगी, और यह सामान्य रूप से विफल नहीं होगी, और समान रूप से लगभग 41 वर्ष की आयु के पी. डब्ल्यू. 3 की स्मृति भी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इससे उनकी याददाश्त में कमी आई होगी। इसलिए, परीक्षण न्यायाधीश P.Ws.2 और 3 के साक्ष्य को स्वीकार करने में पूरी तरह से सही था।

48. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि दो गवाहों, पीडब्लू2 और पीडब्लू3 ने याचिकाकर्ता को पीडित को अपनी मोटरसाइकिल पर ले जाते हुए देखा।

लौटते समय स्कूल बस से नीचे उतरें। पीडब्लू2 और पीडब्लू3 ने भी परीक्षण पहचान परेड के समय गिरफ्तारी पर याचिकाकर्ता की पहचान की, जिसे ठीक से आयोजित किया गया था। इसके अलावा, दोनों गवाहों ने निचली अदालत के समक्ष अपनी-अपनी प्रतिपरीक्षाओं में निर्विवाद साक्ष्य भी प्रदान किए। निचली अदालत ने बच्चे के दिमाग की परिपक्वता को दर्ज करके, एक बाल गवाह, पीडब्लू 2 की गवाही लेने में उचित प्रक्रिया का भी पालन किया, जिसने बच्चे की पहचान भी की।

न्यायालय के समक्ष मोटरबाइक।

एन. डी. ए. आर. @सुंदरराजन बनाम। पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई]

49. उपरोक्त साक्ष्य से पता चलता है कि पीड़ित आखिरी था

याचिकाकर्ता के साथ। इस न्यायालय के समक्ष अपील में, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किया है कि अपहरण के पर्याप्त सबूत थे:

21. हमने पहले विवाद पर विचार किया है

अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील, विवाद के आधार पर

पूर्वगामी अनुच्छेद में देखा गया। प्रच्छन्न प्रस्तुति में

के लिए विद्वान वकील के हाथों में उन्नत अपीलार्थी, हम एक निहित स्वीकृति पाते हैं, अर्थात्, कि

विद्वान वकील स्वीकार करते हैं कि अभियोजन पक्ष ने

मामले के अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री रखी गई ताकि

सुरेश, अभियुक्त के हाथों-अपीलार्थी। वैसा ही रहे। ऐसा कोई निष्कर्ष निकाले बिना हम फिर भी प्रयास करेंगे।

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या अभियोजन सफल रहा था

मृतक सुरेश के अपहरण के तथ्य को स्थापित करते हुए,

अभियुक्त के हाथ-अपीलार्थी।

(जोर दिया गया)

50. इस न्यायालय ने अपील में निर्णय के दौरान इस पर ध्यान दिया

ऊपर चर्चा किए गए साक्ष्य और यह अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता को हत्या का भी दोषी ठहराते हुए पर्याप्त सबूत थे:

" 27. चूंकि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह किया गया है

अपीलार्थी; अभियुक्त-अपीलार्थी पेश करने में सक्षम नहीं हुआ है की रिहाई दिखाने के लिए इस मामले के रिकॉर्ड पर कोई भी सामग्री

सुरेश अपनी हिरासत से। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106,

1872 उस पर जिम्मेदारी डालता है। ऐसी किसी भी सामग्री के अभाव में

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत-अपीलार्थी, यह स्वीकार किया जाना चाहिए, कि

सुरेश की अभिरक्षा अभियुक्त-अपीलार्थी के पास तब तक रही जब तक कि उसकी हत्या कर दी गई। अभियुक्त का उद्देश्य/कारण-अपीलार्थी,

चरम कदम उठाने के लिए, उस फिरौती की मांग की गई थी
इसलिए हम संतुष्ट हैं कि

उसे भुगतान नहीं किया गया था।

वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ, पर्याप्त हैं

इस मामले के अभिलेख पर साक्ष्य, जिसके आधार पर

अभियुक्त के हाथों सुरेश की हत्या का तथ्य

अपीलार्थी खड़ा हो जाता है।

51. इसके अलावा, जैसा कि इस न्यायालय ने उल्लेख किया, भौतिक उद्देश्य थे
याचिकाकर्ता के बयान के आधार पर:

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला, हमारे उपरोक्त निष्कर्ष की पुष्टि करने के लिए। इस संबंध में यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि जब अभियुक्त-अपीलार्थी उसे 30.7.2009 पर हिरासत में लिया गया था, उसने कासिनाथन (PW13) की उपस्थिति में एक इकबालिया बयान दिया था, जिसमें कहा गया था कि उसने सुरेश की गला दबाकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसके शरीर को एक कमरे में डाल दिया गया था।

बोरे और मीरांकुलम टैंक में फेंक दिया। यह था। इसके बाद, अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा यह इंगित करने पर कि सुरेश का शव मीरांकुलम टैंक से बरामद किया गया था। जैसा कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने कहा है, यह एक बोरे में पाया गया था। डॉ. कथिरवेल (पीडब्लू12) ने पोस्टमार्टम कराने के बाद निष्कर्ष निकाला

तत्काल साक्ष्य स्पष्ट रूप से अभियुक्त-अपीलार्थी को स्पष्ट करता है सुरेश की हत्या का अपराधी। इसके अलावा, कासिनाथन (पीडब्लू 13) के बयान से आगे पता चलता है कि सुरेश का स्कूल बैग, किताबें और स्लेट आरोपी-अपीलार्थी के आवास से बरामद किया गया था। इन लेखों की पुष्टि माहेश्वरी (पीडब्लू1) ने सुरेश से संबंधित होने की पुष्टि की थी। तथ्यात्मक और कानूनी दृष्टि से

इसके ऊपर की स्थिति से निपटने के लिए, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने न केवल सुरेश के अपहरण, बल्कि अभियुक्त-अपीलार्थी के हाथों उसकी हत्या को भी स्थापित करने के लिए पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत की थी।

52. सी. डी. आर. के रूप में साक्ष्य केवल उस साक्ष्य की पुष्टि करने के लिए था जो पी. डब्ल्यू. 1 और के बयानों के माध्यम से दिया गया था। उनकी दोनों गवाही न केवल इसके माध्यम से पुष्टि करती हैं लेकिन याचिकाकर्ता के व्यावसायिक बयान के आधार पर मोबाइल फोन की वसूली के माध्यम से भी। उच्च न्यायालय ने चर्चा की

निम्नलिखित पैरा में प्रमाण:

[.....] इस मोड़ पर, P.W.13 ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य की बात की है कि गिरफ्तारी के समय, ए-1 इकबालिया बयान देने के लिए आगे आया था

बयान स्वेच्छा से, और उसी द्वारा दर्ज किया गया था

अन्वेषक। स्वीकार्य भाग को Ex.P9 के रूप में चिह्नित किया गया है जिसके अनुसार उन्होंने तीन सेल फोन बनाए जिनमें से एक में वह नंबर था जिसके माध्यम से उन्होंने पी. डब्ल्यू. 8 को क्रमशः लगभग 9.22 बजे और 9.25 बजे दो फोन कॉल किए।

27.7.2010 , और लगभग 9.39 बजे से पीडब्लू. 1 तक फिरौती की मांग करते हुए। इस मोड़ पर, विद्वान एन. डी. ए. आर. @सुंदरराजन बनाम द्वारा प्रस्तुत तर्क।

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई]

इस बारे में वकील कि क्या एक शंकर जिसने रात 9.22 बजे और 9.25 बजे कॉल किए थे, जीवित था या एक काल्पनिक व्यक्ति, और ए-1 से बरामद सेलफोन, दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार भी उसका नहीं था, को अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि वे योग्यता नहीं रखते हैं। जिस सेलफोन से तीनों कॉल किए गए थे, वह है पी. डब्ल्यू. 8 को रात 9.22 बजे और 9.25 बजे शंकर के नाम से दो कॉल और ए-1 से पी. डब्ल्यू. 1 तक रात 9.39 बजे एक कॉल, बरामद किया गया है और उन कॉल का विवरण सेलफोन में दर्ज किया गया है, और यह वास्तव में पी. डब्ल्यू. 8 द्वारा प्रासंगिक समय के दौरान और ए-1 द्वारा भी प्रासंगिक समय के दौरान रखा गया था। इस प्रकार अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के संज्ञान में लाया है कि Ex.P5 में, कॉल वास्तव में 71 सेकंड के लिए रात 9.22 बजे और 43 सेकंड के लिए रात 9.25 बजे Ex.P5 में पाए गए थे, और एक अन्य कॉल जो की गई थी वह भी उसमें पाई गई है जो कि एम. ओ. 4 सेलफोन से थी।

जो अपीलार्थी/ए-1 से बरामद किया गया था। इन तीन सेल फोन में से एक सेल फोन सिम कार्ड के साथ था और दूसरा बिना सिम कार्ड के दो सेल फोन। अब अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से पता चलेगा कि तीन कॉल

पी. डब्ल्यू. 8 को क्रमशः रात 9.22 बजे और 9.25 बजे दो कॉल किए गए और पी. डब्ल्यू. 1 का नंबर पता लगाने के बाद, तीसरी कॉल पी. डब्ल्यू. 1 को की गई। सभी दस्तावेजी साक्ष्य रखे गए थे।

न्यायालय के समक्ष। इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि पी. डब्ल्यू. 8 का साक्ष्य कि अपीलार्थी/ए-1 पी. डब्ल्यू. 1 का नंबर जानना चाहता था, और फिर उसने पी. डब्ल्यू. 8 को फोन किया और नंबर के बारे में पता चला, और उसके बाद उसने लगभग 9.39 बजे फोन किया।

पी. डब्ल्यू. 1 जैसा कि पी. डब्ल्यू. 1 के साक्ष्य में पाया जा सकता है।

भले ही पूर्वी पी5, सी. डी. आर. होने के नाते, उपरोक्त पैराग्राफ में इस न्यायालय द्वारा भरोसा नहीं किया गया है, अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर नहीं है क्योंकि यह केवल दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों की गवाही की पुष्टि करता है जो बेदाग रहते हैं। उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि दोष पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है याचिकाकर्ता।

53. इसलिए, भले ही एक व्यक्ति द्वारा उठाए गए आधारों में से कोई भी रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटियों के बराबर नहीं है, पुनर्विक्षेपण को देखते हुए, यह भी निर्णायक रूप से कहा जा सकता है कि सभी आधार अभियोजन पक्ष के मामले में कोई उचित संदेह पैदा करने में विफल रहते हैं। 54. तदनुसार, हम समीक्षा क्षेत्राधिकार में विचारण न्यायालय, उच्च न्यायालय और [2023] 5 एस. सी. आर. के समवर्ती निष्कर्षों के साथ सहमत होने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह न्यायालय अपहरण और हत्या के लिए याचिकाकर्ता के अपराध के संबंध में है पीड़ित।

55. याचिकाकर्ता के वकील ने इस अदालत पर पूंजी के संदर्भ में सजा की मात्रा पर पुनर्विचार करने का भी दबाव डाला है।

दंड जिसे विचारण न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया है और उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के निर्णय में अपील में पुष्टि की गई है।

ई. सजा और शमन

56. याचिकाकर्ता के वकील ने विस्तार से तर्क दिया कि मौत की सजा को उचित शमन अभ्यास के बिना पारित किया गया था याचिकाकर्ता की परिस्थितियाँ।

ई. 1. अनिश्चित संदेह सिद्धांत

57. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ऐसे मामलों में मौत की सजा नहीं दी जा सकती है जहां दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो क्योंकि आरोपी के अपराध के बारे में 'स्थायी संदेह' बना रहता है।

58. हालांकि, शत्रुघ्न बबन मेशराम बनाम स्टेट ऑफ

महाराष्ट्र 1, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 'विलंबित संदेह'/'अवशिष्ट संदेह' के सिद्धांत को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा:

77. जब हमारे न्यायशास्त्र में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामलों की बात आती है, तो इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के संदर्भ में अपनाया गया मानक, जैसा कि शरद बर्डहिचंद सारदा और बाद के निर्णयों में देखा गया है, यह है कि परिस्थितियों को न केवल व्यक्तिगत रूप से साबित या स्थापित किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें एक सुसंगत श्रृंखला बनानी चाहिए, ताकि अभियुक्त के अपराध को छोड़कर किसी अन्य परिकल्पना की संभावना को खारिज किया जा सके। इन सिद्धांतों के बल पर, ऐसे मामलों में बोझ पहले से ही अधिक है। एक बार जब उस बोझ को हटा दिया जाता है, तो यह निहित है कि कोई अन्य परिकल्पना या आरोपी की बेगुनाही, पहले से ही खारिज हो जाती है जब मामले को अपराध के निष्कर्ष को वापस करने के बाद सजा के चरण में लिया जाता है। इसलिए, सैद्धांतिक रूप से "अवशिष्ट संदेह" की अवधारणा या सिद्धांत का परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले में कोई स्थान नहीं है। वास्तव में, अवशिष्ट संदेह के सिद्धांत को अमेरिका द्वारा कभी स्वीकार नहीं किया गया था

उच्चतम न्यायालय, जैसा कि पहले चर्चा की गई थी।

78. हालाँकि, जैसा कि कालू खान में संक्षेप में कहा गया है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामलों से निपटने के दौरान, मृत्यु अधिरोपित करने के लिए

16 2021 (1) एस. सी. सी. 596 सुंदर @सुंदरराजन बनाम। पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

वाक्य, उच्च या सख्त मानक पर जोर दिया जाना चाहिए। द. मृत्युदंड से संबंधित मामलों में अपनाया जाने वाला दृष्टिकोण,

इसलिए निकाले गए सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। पैरा 50 में यहाँ ऊपर और तत्काल बात इसलिए होनी चाहिए

उन सिद्धांतों के आलोक में माना जाता है।

(जोर दिया गया)

59. तदनुसार, अवशिष्ट या विलंबित संदेह का तर्क करता है

याचिकाकर्ता के बचाव में नहीं आते हैं। बल्कि, तत्काल मामले में अपीलीय निर्णय के दौरान, शरद बर्डहिचंद सारदा में निर्धारित मानक और बाद के मामलों को इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया और इन सिद्धांतों के संदर्भ में तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद ही न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अपराध को बरकरार रखा। इस अदालत ने नोट किया कि:

24. पूर्ववर्ती तीनों में देखे गए साक्ष्य के आधार पर

पैराग्राफ, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि आरोपी

अपीलार्थी की पहचान ठोस साक्ष्य के माध्यम से उस व्यक्ति के रूप में की गई थी सुरेश के स्कूल से उतरने पर उसे कौन ले गया था

27.7.2009 पर वैन। द. सुरेश के अपहरण का तथ्य

अभियुक्त-अपीलार्थी, इसलिए, विधिवत रूप से स्थापित है।

[.....]

27. [.....] इसलिए हम संतुष्ट हैं कि तथ्यों में और वर्तमान मामले की परिस्थितियों, पर पर्याप्त सबूत है

इस मामले का अभिलेख, जिसके आधार पर तथ्य भी

अभियुक्त के हाथों सुरेश की हत्या-अपीलार्थी खड़ा है स्थापित किया गया।

60. यह न्यायालय पहले ही पुष्टि करने के लिए प्रासंगिक मानक लागू कर चुका है।

किसी मामले में अपील में याचिकाकर्ता का अपराध जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और इस न्यायालय के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह अपने सीमित दायरे को देखते हुए एक बार फिर समीक्षा अधिकार क्षेत्र में साक्ष्य का मूल्यांकन करे।

ई. 2. विचारण न्यायालय में सजा और शमन और

अपीलीय न्यायालय

61. याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि भले ही याचिकाकर्ता का

अपराध की पुष्टि की गई, निचली अदालत और अपीलीय अदालतें [2023] 5 एस. सी. आर. का निर्णय लेते समय याचिकाकर्ता के सुधार की संभावना सहित प्रासंगिक उग्र और कम करने वाली परिस्थितियों पर उचित रूप से विचार करने में विफल रहीं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सजा पर। वकील ने आग्रह किया कि याचिकाकर्ता को नहीं होना चाहिए

मृत्युदंड दिया गया है और एक उचित शमन अभ्यास करने में अदालतों की विफलता को देखते हुए इसे कम किया जाना चाहिए।

62. इस न्यायालय की मिसाल के अनुसार, इस बात पर चर्चा हुई है कि क्या सजा के मुद्दे पर एक अलग सुनवाई अनिवार्य है

मृत्युदंड योग्य अपराध के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धि दर्ज करने के बाद। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 235 में इस प्रकार कहा गया है:

235. दोषमुक्त या दोषसिद्धि का निर्णय।

(1) दलीलों और कानून के बिंदुओं (यदि कोई हो) को सुनने के बाद, न्यायाधीश मामले में निर्णय देगा।

(2) यदि अभियुक्त दोषी ठहराया जाता है, तो न्यायाधीश, जब तक कि वह धारा 360 के प्रावधानों के अनुसार आगे नहीं बढ़ता है, अभियुक्त को सजा के प्रश्न पर सुनेगा, और फिर उसे कानून के अनुसार सजा देगा।

63. सांता सिंह बनाम पंजाब राज्य 1 3 मामले में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने अलग से सजा सुनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

सी. आर. पी. सी. की धारा 235 (2) को ध्यान में रखते हुए सुनवाई और नोट किया कि सजा का चरण अपराधिक न्याय देने की प्रक्रिया में उतना ही महत्वपूर्ण चरण था जितना कि अपराध का निर्णय।

64. बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1 9 9 19 में संविधान पीठ के फैसले में बहुमत के फैसले ने एक के महत्व को दोहराया सजा सुनाना। न्यायालय ने कहा कि:

151. सी. आर. पी. सी., 1973 की धारा 354 (3), 1898 की संहिता के अंतर्गत विधायी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है, जो लागू है।

1 अप्रैल, 1974 से ठीक पहले, जिसके अनुसार हत्या और दंड संहिता के तहत कुछ अन्य मृत्युदंड के अपराधों के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास दोनों की वैकल्पिक सजाएं सामान्य सजाएं थीं। अब इस बदली हुई विधायी नीति के अनुसार, जो धारा 354 (3) के तहत पेटेंट है, दंड संहिता के तहत हत्या और छह अन्य मृत्युदंड के अपराधों के लिए सामान्य सजा आजीवन कारावास (या कारावास) है।

वर्षों की अवधि के लिए) और मृत्युदंड एक अपवाद है।

18 1976 (4) एससीसी 190

19 1980 (2) एस. सी. सी. 684 सुंदर @सुंदरराजन बनाम। पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई]

[.....]

152. इस संदर्भ में, हम धारा 235 (2) पर भी ध्यान दे सकते हैं।

1973 का कोड, क्योंकि यह न केवल स्पष्ट करता है, क्या के अनुसार

जगमोहन के मामले में निर्णय की योजना में निहित था

संहिता, लेकिन दो के लिए प्रदान करके परीक्षण को भी विभाजित करता है

सुनवाई, एक पूर्व-दोषसिद्धि चरण में और दूसरा

पूर्व-वाक्य चरण।

[.....]

163. [.....] अब, धारा 235 (2) एक द्विभाजित परीक्षण का प्रावधान करती है।

सजा की सुनवाई, किस स्तर पर, वह रिकॉर्ड पर ला सकता है सामग्री या साक्ष्य, जो कड़ाई से प्रासंगिक नहीं हो सकता है

या जांच के तहत विशेष अपराध से संबंधित है, लेकिन फिर भी, रेखांकित नीति के अनुरूप है

धारा 354 (3) में सजा के चयन पर असर पड़ता है। वर्तमान में धारा 235 (2) के साथ पठनीय विधायी नीति

354 (3) यह है कि सजा की डिग्री तय करने या बनाने में विभिन्न अपराधों के लिए सजा का चयन, जिसमें एक के तहत अपराध शामिल है

विशेष अपराध से जुड़ा हुआ है, लेकिन देय भी देता है अपराधी की परिस्थितियों पर विचार करना।

(जोर दिया गया)

65. एक अलग सुनवाई की इस आवश्यकता को दोहराया गया था

मुनियप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य 20 जहाँ न्यायालय ने नोट किया

सजा पर एक अलग सुनवाई के प्रावधान का पालन करने का महत्व न केवल एक औपचारिकता के रूप में बल्कि भावना और सार में ऐसी जानकारी की जांच करने का वास्तविक प्रयास करना जिसका सजा के प्रश्न पर प्रभाव पड़ सकता है।

66. अलाउद्दीन मियां बनाम बिहार राज्य 2 1 में, दो न्यायाधीशों की पीठ

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्राकृतिक न्याय के नियमों को संतुष्ट करने के लिए सजा सुनाने की आवश्यकता है; कि यह अनिवार्य है और केवल औपचारिकता नहीं है। न्यायालय ने कहा:

10. अभियुक्त की सुनवाई की आवश्यकता का उद्देश्य है

प्राकृतिक न्याय के नियम को संतुष्ट करना। यह एक मौलिक है

निष्पक्ष खेल की आवश्यकता कि अभियुक्त जो अब तक था

20 1981 (3) एससीसी 11

21 1989 (3) एससीसी 5 [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपराध के प्रश्न पर अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना

दोषी पाए जाने पर यह पूछा जाना चाहिए कि क्या उसके पास सजा के सवाल पर कहने के लिए कुछ है या कोई सबूत है। यह और भी आवश्यक है क्योंकि अदालतों को आम तौर पर सजा सुनाने के मामले में विवेक की एक विस्तृत शृंखला से चुनाव करने की आवश्यकता होती है। विधायिका द्वारा अधिरोपित की जाने वाली सही सजा निर्धारित करने में अदालत की सहायता करना।

धारा 235 में उप-धारा (2) को प्रस्तुत किया गया। ने कहा कि इसलिए प्रावधान एक दोहरे उद्देश्य को संतुष्ट करता है; यह अभियुक्त के अनुसार सजा के प्रश्न पर सुनवाई के अवसर द्वारा प्राकृतिक न्याय के नियम को संतुष्ट करता है और साथ ही अदालत को दी जाने वाली सजा का चयन करने में मदद करता है। चूंकि प्रावधान का उद्देश्य अभियुक्त को सजा के प्रश्न से संबंधित सभी प्रासंगिक सामग्री को अदालत के समक्ष रखने का अवसर देना है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि प्रावधान हितकर है और इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से अनिवार्य है और इसे केवल औपचारिकता के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

[.....] जीवन या मृत्यु के मामले में, जैसा कि पहले कहा गया है, पीठासीन अधिकारी को अभियुक्त के वैधानिक अधिकार के लिए उच्च स्तर की चिंता दिखानी चाहिए और सजा का चुनाव करने से पहले इसे केवल औपचारिकता के रूप में नहीं मानना चाहिए। यदि विकल्प चुना जाता है, जैसा कि इस मामले में, अभियुक्त को प्रभावी और वास्तविक विकल्प दिए बिना।

अपनी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करने का अवसर

अदालत के समक्ष परिस्थितियों को कम करने और बढ़ाने आदि की पृष्ठभूमि में, सजा पर अदालत का निर्णय कमजोर होगा। हमें शायद ही यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि कई मामलों में एक सजा

विशुद्ध रूप से अपराध के मामले की तुलना में अपराधी और उसके परिवार के सदस्यों पर निर्णय के कहीं अधिक गंभीर परिणाम होते हैं।

प्रशासनिक निर्णय; इसलिए, निष्पक्ष खेल का सिद्धांत बाद वाले की तुलना में पहले वाले के मामले में अधिक जोश के साथ लागू होना चाहिए। अगर सुनवाई किए बिना प्रशासनिक निर्णय लिया जाता है, तो उसे आम तौर पर प्राकृतिक न्याय के नियम के उल्लंघन के रूप में खारिज कर दिया जाता है। इसी तरह बिना सजा सुनाए निर्णय लिया गया संहिता की धारा 235 की उप-धारा (2) की आवश्यकताओं का अक्षर और भाव में पालन करने पर भी ऐसा ही होगा और इसे एक उपयुक्त आदेश द्वारा प्रतिस्थापित करना पड़ सकता है।

सुंदर @सुंदरराजन बनाम। पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई]

सजा सुनाने वाली अदालत को इस सवाल पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और

दोषसिद्धि दर्ज करने से मामले को भविष्य की तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है और अभियोजन पक्ष के साथ-साथ बचाव पक्ष दोनों को बुलाएंगे

के प्रश्न पर प्रासंगिक सामग्री रखने के लिए

वाक्य के पहले और उसके बाद वाक्य का उच्चारण करें।

अपराधी पर थोपा जाना।

(जोर दिया गया)

67. अलग से सजा सुनाने का महत्व

दोषसिद्धि दर्ज करने के बाद अभियुक्त को अंगुस्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य 2, मल्लिकयत सिंह बनाम पंजाब राज्य 23 में दोहराया गया। दत्तराय बनाम महाराष्ट्र राज्य 2 4.

68. दूसरी ओर, इसके निर्णय भी हुए हैं

न्यायालय जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायालय एक अलग सुनवाई के लिए स्थगित कर सकता है, उसी दिन की सजा ने धारा के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया 235 (2) सी. आर. पी. सी. और अपने आप में सजा को दूषित नहीं किया। इस तर्क को डगडू बनाम राज्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों में अपनाया गया था।

महाराष्ट्र ", तरलोक सिंह बनाम पंजाब राज्य 2 और रामदेव चौहान बनाम असम राज्य 27

69. सुओ मोटू में डब्ल्यू. पी. (सीआरएल।) नं. 1/2022 शीर्षक पुनः फ्रेमिंग

संभावित कम करने वाली स्थितियों के बारे में दिशानिर्देश

मृत्युदंड अधिरोपित करते समय विचार किए जाने पर, इस न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2) की व्याख्या में दृष्टिकोण में अंतर पर ध्यान दिया और प्रश्न को एक बड़ी पीठ के विचार के लिए भेजा। जबकि इसने एक अलग और प्रभावी सजा सुनाने की सुनवाई की अनुमति देने के लिए निचली अदालत के स्तर पर 'पर्याप्त समय' पर संघर्ष पर ध्यान दिया, इसने नोट किया कि सभी निर्णयों में निम्नलिखित सामान्य आधार भी थे:

27. इन सभी निर्णयों के माध्यम से चलने वाला सामान्य धागा है

व्यक्त स्वीकृति कि सार्थक, वास्तविक और

22 1989 (3) एससीसी 33

23 1991 (4) एस. सी. सी. 341

24 2020 (14) एससीसी 290

25 1977 (3) एससीसी 68

26 1977 (3) एससीसी 218

27 2001 (5) एससीसी 714 [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अभियुक्त को प्रभावी सुनवाई प्रदान की जानी चाहिए, के प्रश्न के लिए प्रासंगिक सामग्री जोड़ने का अवसर

सजा सुनायो।

70. वर्तमान मामले में, सजा सुनाने से संबंधित निचली अदालत का फैसला इंगित करता है कि एक सार्थक, वास्तविक और प्रभावी सुनवाई

याचिकाकर्ता को वहन नहीं किया गया था।

71. ट्रायल कोर्ट ने कोई अलग सुनवाई नहीं की

सजा सुनाई गई और किसी भी शमनकारी परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा गया। मृत्युदंड देने से पहले याचिकाकर्ता से संबंधित। अपने फैसले के दौरान, निचली अदालत ने मौत की सजा देने से पहले केवल निम्नलिखित पर ध्यान दिया:

वर्तमान परिस्थितियों में फिरौती के लिए बच्चों और बड़ों का अपहरण करना और उनकी हत्या करना आम बात हो गई है यदि अपेक्षित फिरौती प्राप्त नहीं होती है। इस स्थिति में जब तक फिरौती के लिए अपहरणकर्ताओं को अत्यधिक दंड के साथ दंडित नहीं किया जाता है, भविष्य में फिरौती के लिए बच्चों और बड़ों का अपहरण बढ़ जाएगा और समाज के पूरी तरह से खराब होने का खतरा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए इन सभी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि प्रथम को पुरस्कार देना न्याय के हित में होगा।

अत्यधिक दंड का आरोप लगाया। इतना ही नहीं अदालत ने मृतक लड़के की मां को अदालत में अपने बेटे की मौत पर अदालत में खूब रोते और रोते हुए देखा और अदालत में दर्शकों के रोते हुए दृश्य को भी कोई नहीं भूल सकता। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए

दंड; न्याय के हित में।

72. उच्च न्यायालय ने इस कृत्य की वीभत्स और निर्दयी प्रकृति को ध्यान में रखा। इसने उन उदाहरणों को दोहराया जिसमें कहा गया था कि मृत्युदंड केवल दुर्लभतम मामलों में ही दिया जाना है। हालाँकि, इसने विशेष रूप से याचिकाकर्ता पर असर डालने वाली किसी भी कम करने वाली परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया। इसने केवल यह अभिनिर्धारित किया कि:

नरमी अपराध प्रणाली का मजाक होगा। इसलिए, विचारण न्यायाधीश द्वारा अधिरोपित मृत्युदंड की पुष्टि की जानी है,

और तदनुसार, इसकी पुष्टि की जाती है।

एन. डी. ए. आर. @सुंदरराजन बनाम। पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई]73. इस न्यायालय ने ई की गंभीर परिस्थितियों की विस्तार से जांच की। हालांकि, जहां तक कम करने वाली परिस्थितियों का संबंध है, यह

मैं वह:

31. जहाँ तक उपरोक्त भयावह परिस्थितियों का संबंध है, अभियुक्त-अपीलार्थी का विद्वान वकील हमें यह भी नहीं बता सका कि

एकल शमनकारी परिस्थिति। इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों पर भी, अभियुक्त-अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा किए गए निर्णयों में, हमारे पास नहीं है

इसके द्वारा दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त निष्कर्ष विक्रम सिंह और अन्य में न्यायालय बनाम पंजाब राज्य, (2010) 3 एस. सी. सी. 56, जिसमें समान परिस्थितियों में (निश्चित रूप से, यहाँ की परिस्थितियाँ उक्त मामले की तुलना में बहुत गंभीर हैं), इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड को बरकरार रखा था।

75. इस न्यायालय द्वारा अपील में ली गई गंभीर परिस्थितियों के संदर्भ में, हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है -पंखों की स्थिति:

30. [.....]

(vii) फिरौती के लिए विशेष बच्चे के अपहरण का विकल्प,

अच्छी तरह से योजनाबद्ध और सचेत रूप से प्रेरित था। मृतक के माता-पिता के चार बच्चे थे-तीन बेटियाँ और एक बेटा।

एकमात्र पुरुष बच्चे का अपहरण उसके माता-पिता के मन में अधिकतम भय पैदा करने के लिए था। एकमात्र पुरुष बच्चे की उद्देश्यपूर्ण हत्या, मृतक के माता-पिता के लिए गंभीर परिणाम है। अपने एकमात्र पुरुष बच्चे को खोने के लिए माता-पिता के लिए पीड़ा, जिनके पास होगा

पारिवारिक वंशावली को आगे बढ़ाते हुए, और उनसे अपने बुढ़ापे के दौरान उन्हें देखने की उम्मीद की जाती है, यह अथाह है। पीड़ित पक्ष को हुई अत्यधिक पीड़ा, निश्चित रूप से उग्रता को बढ़ाती है परिस्थितियाँ।

हम यह ध्यान रखना चाहते हैं कि बच्चे के लिंग को एक संवैधानिक अदालत द्वारा एक उत्तेजक परिस्थिति के रूप में नहीं माना जा सकता है।

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक छोटे बच्चे की हत्या निर्विवाद रूप से एक गंभीर अपराध है और इस तरह के पीड़ित की कम उम्र के साथ-साथ वह आघात जो इसके कारण होता है पूरा परिवार अपने आप में, निस्संदेह, एक परेशान करने वाली स्थिति है। ऐसी परिस्थिति में, संवैधानिक न्यायालय के लिए यह मायने नहीं रखता कि छोटा बच्चा पुरुष बच्चा था या महिला बच्चा। हत्या भी उतनी ही दुखद बनी हुई है। अदालतों को इस धारणा को आगे बढ़ाने में भी शामिल नहीं होना चाहिए कि केवल एक पुरुष बच्चा ही पारिवारिक वंशावली को आगे बढ़ाता है या वृद्धावस्था में माता-पिता की सहायता करने में सक्षम होता है। इस तरह की टिप्पणियां अनैच्छिक रूप से पितृसत्तात्मक मूल्य निर्णयों को आगे बढ़ाती हैं जिनसे अदालतों को संदर्भ की परवाह किए बिना बचना चाहिए।

76. राजेन्द्र प्रल्हादराव वासनिक बनाम महाराष्ट्र राज्य 28 वाले मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस न्यायालय के मामलों पर ध्यान दिया जो इस संभावना पर विचार करने के महत्व को रेखांकित करता है - दोषी अभियुक्त को मौत की सजा सुनाने से पहले उसका सुधार और पुनर्वास। अदालत ने कहा:

43. इस स्तर पर, हमें बच्चन सिंह की ओर ध्यान देना चाहिए और संभावना, संभावना और असंभवता के बीच अंतर करना चाहिए।

सुधार और पुनर्वास। बचन सिंह चाहते हैं कि हम सुधार और पुनर्वास की संभावना पर विचार करें, न कि इसकी संभावना पर।

या इसकी असंभवता।

[...]

45. इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा निर्धारित कानून स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से आदेश देता है कि एक दोषी को सुधारने की संभावना (संभावना या असंभवता या असंभवता नहीं) और मृत्युदंड देने से पहले अदालतों द्वारा समाज में पुनर्वास पर गंभीरता से और ईमानदारी से विचार किया जाना चाहिए। यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 (3) की "विशेष कारणों" की आवश्यकता के अधिदेशों में से एक है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करना शामिल है। इस अधिदेश को प्रभावी बनाने के लिए, अभियोजन पक्ष पर यह दायित्व है कि वह अदालत के समक्ष साबित करे,

साक्ष्य के माध्यम से, कि संभावना है कि दोषी

सुधार या पुनर्वास नहीं किया जा सकता है। यह अन्य बातों के साथ-साथ, जेल में उसके आचरण के बारे में सामग्री, जेल के बाहर उसके आचरण, अगर वह कुछ समय से जमानत पर है, तो उसके मानसिक बनावट के बारे में चिकित्सा साक्ष्य, उसके परिवार के साथ संपर्क आदि को रिकॉर्ड में लाकर प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह, दोषी इन मुद्दों पर सबूत पेश कर सकता है।

साथ ही।

28 2019 (12) एस. सी. सी. 460 एन. डी. ए. आर. @सुंदरराजन बनाम

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई]

कम से कम आजीवन कारावास की सजा काटना।
पुनर्एकीकरण पर विचार नहीं किया जा सकता है।

47. दोषी के समाज में सुधार, पुनर्वास और

अत्यधिक जोर दिया। बचन सिंह तक, जोर दिया गया

अदालतों द्वारा मुख्य रूप से अपराध की प्रकृति, इसकी क्रूरता और गंभीरता पर था। बचन सिंह ने सजा देने की प्रक्रिया को परिप्रेक्ष्य में रखा और दोषी के सुधार या पुनर्वास पर विचार करने की आवश्यकता की शुरुआत की।

संविधान पीठ द्वारा व्यक्त विचार के बावजूद, वहाँ है

कई उदाहरण हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख बरियार और संगीत वी में किया गया है। हरियाणा राज्य जहाँ अपराध को प्रधानता देने और अपराधी पर विचार करने की प्रवृत्ति है।

कुछ हद तक माध्यमिक तरीके से। जैसा कि संगीत में कहा गया है, "सजा देने की प्रक्रिया में अपराध और अपराधी दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।" इसलिए, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अपराधी, चाहे वह कितना भी निर्दयी क्यों न हो, फिर भी एक इंसान है। अपने अपराध के बावजूद गरिमापूर्ण जीवन का हकदार है और है। इसलिए, यह अभियोजन पक्ष और अदालतों को यह निर्धारित करना है कि क्या ऐसे व्यक्ति को, उसके अपराध के बावजूद, सुधार और पुनर्वास किया जा सकता है। पाने के लिए और

इस जानकारी का विश्लेषण करना निश्चित रूप से एक आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी इसे किया जाना चाहिए। पुनर्वास की प्रक्रिया यह भी सरल नहीं है क्योंकि इसमें दोषी का समाज में सामाजिक पुनर्एकीकरण शामिल है। बेशक, उपलब्ध कराई गई किसी भी जानकारी और विशेषज्ञों द्वारा इसके विश्लेषण के बावजूद

अभिलेख पर साक्ष्य, ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहाँ दोषी का सामाजिक एकीकरण संभव नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होना चाहिए। ऐसा होने पर लंबी अवधि के कारावास का विकल्प स्वीकार्य है।

(जोर दिया गया)

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

77. बचन सिंह में निर्धारित कानून को पूरा करना आवश्यक है

मृत्युदंड देने के लिए 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' की आवश्यकता होती है

हम यह निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि दोषी किसी भी प्रकार की सुधारात्मक पुनर्वास योजना के लिए उपयुक्त नहीं है। जैसा कि संतोष कुमार सतीशभूषण में उल्लेख किया गया है

आर बनाम महाराष्ट्र राज्य 2 9, इसके लिए इससे आगे देखने की आवश्यकता है

ई अपराधी पर भी:

66. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, दुर्लभतम उक्ति इस ओर संकेत करती है।
विकल्प के बीच अंतर

मृत्युदंड और

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या सजा के रूप में आजीवन कारावास होगा
पूरी तरह से तर्कहीन होना और

तथ्यों में व्यर्थ और

मामले की परिस्थितियाँ? जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, जीवन
व्यर्थ कहा जा सकता है, केवल तभी जब

कारावास को पूरी तरह से

सुधार के सजा देने के उद्देश्य को कहा जा सकता है

असंभव है। इसलिए, दूसरे अपवाद को संतुष्ट करने के लिए

दुर्लभतम सिद्धांत के लिए, अदालत को प्रदान करना होगा

स्पष्ट सबूत है कि दोषी किसी भी प्रकार के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है

सुधारात्मक और पुनर्वास योजना। यह विश्लेषण कर सकते हैं

केवल कठोरता के साथ किया जाए जब अदालत पर ध्यान केंद्रित किया जाए

अपराधी से संबंधित परिस्थितियाँ, अन्य के साथ
निष्कर्ष नहीं है,

परिस्थितियाँ। यह समझने के लिए एक आसान

लेकिन बचन सिंह ने परिचय देकर स्तर को बहुत ऊँचा कर दिया

दुर्लभतम सिद्धांत।

(जोर दिया गया)

78. इस न्यायालय द्वारा अनिल बनाम राज्य के मामले में भी इसी तरह के मुद्दे को रेखांकित किया गया था।

30 जहाँ न्यायालय ने नोट किया कि:

33. बचन सिंह में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है,

संभावना है कि अभियुक्त आपराधिक कृत्य नहीं करेगा
खतरा बनेगी '

हिंसा जो समाज के लिए एक निरंतर

एक प्रासंगिक परिस्थिति, जिसे बहुत महत्व दिया जाना चाहिए
में आगे व्यक्त किया गया था।

सजा का निर्धारण। यह संतोष

कुमार सतीशभूषण बरियारा। कई बार, जबकि

सजा का निर्धारण करते हुए, अदालतें इसे हल्के में लेती हैं,

एक विशेष मामले के तथ्यों को देखते हुए, कि अभियुक्त

9 (6) एससीसी 498

4 (4) एस. सी. सी. 69 सुंदर @सुंदरराजन बनाम। पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

समाज के लिए खतरा होगा और इसकी कोई संभावना नहीं है सुधार और पुनर्वास का, जबकि यह कर्तव्य है

अदालत उन कारकों का पता लगाने के लिए, और राज्य बाध्य है

संभावना के पक्ष और विपक्ष में सामग्री प्रस्तुत करें

अभियुक्त का सुधार और पुनर्वास। तथ्यों,

जिसे अदालतें किसी दिए गए मामले में निपटती हैं, वह नहीं हो सकता है

इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आधार, जो पहले से ही

कहा गया है, अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता है। इसलिए हम निर्देश देते हैं कि आपराधिक अदालतें, धारा जैसे अपराधों से निपटने के दौरान

302 आई. पी. सी., दोषसिद्धि के बाद, उचित मामलों में, एक

यह निर्धारित करने के लिए रिपोर्ट करें कि क्या अभियुक्त में सुधार किया जा सकता है या पुनर्वासित, जो तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है

हर मामले में।

(जोर दिया गया)

79. इस पर विचार करने के लिए ऐसी कोई जांच नहीं की गई है।

याचिकाकर्ता के मामले में ऊपर वर्णित कारकों में से। न तो निचली अदालत ने और न ही अपीलीय अदालतों ने निर्णायक रूप से किसी भी कारक पर गौर किया है

बता दें कि याचिकाकर्ता में सुधार या पुनर्वास नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, अदालतों ने मौत की सजा देने के लिए अपराध की वीभत्स प्रकृति को दोहराया है। अपील में, इस न्यायालय ने केवल यह उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता के वकील परिस्थितियों को कम करने की ओर इशारा नहीं कर सके और मौत की सजा को बरकरार रखा। राज्य को सभी सामग्री को समान रूप से रखना चाहिए और अभिलेख पर स्थित परिस्थितियाँ सुधार की संभावना पर निर्भर करती हैं। ऐसी कई सामग्री और पहलू राज्य की जानकारी में हैं जिनके पास दोषी ठहराए जाने से पहले और बाद में आरोपी की अभिरक्षा थी। इसके अलावा, अदालत इस प्रक्रिया में उदासीन नहीं हो सकती है।

न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है कि सुधार की संभावना के आधार पर न्यायसंगत सजा का निर्णय लेने के लिए ऐसी सामग्री उसे उपलब्ध कराई जाए।

80. मोफिल खान के मामले में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ भी थी

विशेष रूप से, इसने बताया कि यह अदालत का कर्तव्य था कि वह संभावित कम करने वाली परिस्थितियों पर गौर करे, भले ही आरोपी चुप हो। अदालत ने कहा कि वह:

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मोहम्मद में। मन्नान वी. बिहार राज्य जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मृत्युदंड की चरम सजा देने से पहले, न्यायालय ने

स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि मृत्युदंड अनिवार्य है, अन्यथा

दोषी समाज के लिए खतरा होगा, और यह कि कोई नहीं है

देने के बाद दोषी के सुधार या पुनर्वास की संभावना दोषी को सुनवाई का एक प्रभावी, सार्थक, वास्तविक अवसर

वाक्य के प्रश्न पर, सामग्री का उत्पादन करके। सुनवाई

सजा प्रभावी होनी चाहिए और भले ही आरोपी

चुप रहता है, न्यायालय बाध्य और कर्तव्यबद्ध होगा

प्रासंगिक कारकों को उजागर करने के लिए।

10. यह एक सुव्यवस्थित कानून है कि सुधार की संभावना

और दोषी का पुनर्वास एक महत्वपूर्ण कारक है जो

कारकों और संभावना के संबंध में उन पर विचार करें सुधार, भले ही अभियुक्त चुप रहे। एक जांच

यह इंगित करेगा कि मृत्युदंड लेने से लगाया जाता है अपराध की क्रूरता को ध्यान में रखते हुए। कोई संदर्भ नहीं है

याचिकाकर्ताओं के सुधार की संभावना, न ही राज्य के पास है

यह साबित करने के लिए कोई सबूत जुटाया कि ऐसी कोई संभावना नहीं है याचिकाकर्ताओं के संबंध में। हम सामाजिक की जांच की है

आपराधिक पृष्ठभूमि, उनके परिवार और समुदाय द्वारा दायर हलफनामे सदस्य जिनके साथ वे भावनात्मक संबंध साझा करना जारी रखते हैं और

उनके आचरण पर जेल अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र

उनके 14 साल के लंबे कारावास के दौरान। सभी को ध्यान में रखते हुए ऊपर, यह नहीं कहा जा सकता है कि सुधार की कोई संभावना नहीं है

याचिकाकर्ताओं का, कम के वैकल्पिक विकल्प को बंद करना

सजा देना और मौत की सजा को अनिवार्य बनाना।

(जोर दिया गया)

81. अदालत का कर्तव्य है कि वह कम करने वाली परिस्थितियों की जांच करे

सुधार और पुनर्वास की संभावना को पूर्ववत् करने के लिए

ई मृत्युदंड को लागू करने को कई मामलों में उजागर किया गया है। इस न्यायालय के न्यायाधीश। इसके बावजूद, वर्तमान मामले में ऐसी कोई जांच नहीं की गई है।

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई]

निष्पादित किया गया था और अपराध की गंभीर प्रकृति एकमात्र कारक थी जिस पर मृत्युदंड देते समय विचार किया गया था।

जानकारी दी। 83. 26 सितंबर 2021 को एक हलफनामे के माध्यम से, तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में पुलिस उप निरीक्षक कम्मपुरम

उसने अदालत को सूचित किया है कि याचिकाकर्ता का आचरण संतोषजनक रहा है और वह किसी अन्य मामले में शामिल नहीं रहा है। इसके अलावा, वह प्रणालीगत उच्च रक्तचाप से पीड़ित है और जेल अस्पताल से दवा ले रहा है। याचिकाकर्ता ने जेल में अपने समय के दौरान खाद्य खानपान में डिप्लोमा भी प्राप्त किया है।

84. अलग से, इस न्यायालय को केंद्रीय कारागार के कारागार अधीक्षक से 8 नवंबर 2018 का एक दस्तावेज भी प्राप्त हुआ।

कुड्डालोर-4 सहायक पंजीयक, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पत्र के जवाब में जेल अधिकारियों से निर्देश मांगने के आदेश को संप्रेषित करते हुए। विशेष रूप से, इस दस्तावेज़ में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने भागने की कोशिश की 6 नवंबर 2013 को जेल से। यह चिंताजनक है कि प्रत्यर्थी 26 सितंबर 2021 के हलफनामे में इसे शामिल करने में विफल रहा है।

जानकारी दी।

85. भौतिक तथ्यों का खुलासा न करना भ्रामक है।

यह न्यायालय और न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने का प्रयास। 2021 की सुओ मोटू अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 3 का शीर्षक पुनः वास्तव में, इस न्यायालय ने न्यायालय की अवमानना के बराबर के भौतिक तथ्यों को दबाने/छिपाने वाले झूठे बयानों वाले हलफनामों और उपक्रमों को प्रस्तुत करने से संबंधित इस न्यायालय की पूर्ववर्ती रेखा पर चर्चा की:

15. इस प्रकार यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक व्यक्ति जो न्यायालय के समक्ष गलत बयान देता है और न्यायालय को धोखा देने का प्रयास करता है,

न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करता है और दोषी है

न्यायालय की अवमानना। उपरोक्त निकाले गए भाग से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय के पास न केवल अंतर्निहित [2023] 5 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शक्ति लेकिन यह अपने कर्तव्य में विफल होगा यदि कथित अवमानक के साथ प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए अवमानना क्षेत्राधिकार में व्यवहार नहीं किया जाता है अदालत।

86. याचिकाकर्ता की लिखित दलीलों के अनुसार, वह लगभग 24 वर्ष के थे जब 30 पर निचली अदालत का फैसला सुनाया गया था। जुलाई 2010। वह 2009, 13 साल से जेल में है। उसके पास कोई पूर्व नहीं था

पूर्ववृत्त और जेल अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें नहीं किया गया है

किसी अन्य मामले में शामिल। हालांकि, जेल अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के जेल से भागने के प्रयास को इस अदालत के संज्ञान में लाया है। 87. समीक्षा याचिका में, यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता कम करने वाली परिस्थितियों के बारे में नहीं बता सका

वकील और उसके रिश्तेदारों को सजा सुनाने का उसका निर्णय, जो गरीब और अशिक्षित थे, उनके लिए मामले को ठीक से नहीं लड़ सके। तथ्य यह है कि किसी भी कम करने वाली परिस्थितियों को किसी से पहले नहीं रखा गया था

अपीलीय न्यायालय।

88. इन विवरणों के आधार पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि सुधार की कोई संभावना नहीं है, भले ही याचिकाकर्ता ने एक

भयानक अपराध। हमें कई कम करने वाले कारकों पर विचार करना चाहिए: याचिकाकर्ता का कोई पूर्व इतिहास नहीं है, जब उसने अपराध किया था तब उसकी आयु 23 वर्ष थी

और 2009 से जेल में है जहाँ उसका आचरण संतोषजनक रहा है, सिवाय 2013 में जेल से भागने के प्रयास के। याचिकाकर्ता प्रणालीगत उच्च रक्तचाप के एक मामले से पीड़ित है और उसने खाद्य खानपान में डिप्लोमा के रूप में कुछ बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास किया है। जेल में एक व्यवसाय के अधिग्रहण का लाभप्रद जीवन जीने की उसकी क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

89. उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि भले ही याचिकाकर्ता द्वारा किया गया अपराध निर्विवाद रूप से गंभीर है

और अक्षम्य, उसे दी गई मौत की सजा की पुष्टि करना उचित नहीं है। जैसा कि हमने चर्चा की है, 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' सिद्धांत के लिए आवश्यक है कि मौत की सजा केवल स्वीकार करके नहीं दी जाए

अपराध की गंभीर प्रकृति को ध्यान में रखें, लेकिन केवल तभी जब किसी अपराधी में सुधार की कोई संभावना न हो।

सुंदर @सुंदरराजन बनाम। पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

90. हालाँकि, हम यह भी जानते हैं कि आजीवन कारावास की सजा

कारावास माफी के अधीन है। हमारी राय में, यह नहीं होगा याचिकाकर्ता द्वारा किए गए वीभत्स अपराध को देखते हुए पर्याप्त है।

91. इस अदालत को पहले भी ऐसी ही स्थितियों का सामना करना पड़ा है जहां

इसने देखा है कि कुछ मामलों में छूट के साथ आजीवन कारावास की सजा अपर्याप्त हो सकती है। उदाहरण के लिए, स्वामी श्रद्धानंद (2) @मुरली मनोहर मिश्रा बनाम कर्नाटक राज्य 3 1 न्यायालय में

नोट किया कि:

92. इस मामले को थोड़े अलग कोण से देखा जा सकता है।

अपर्याप्त। जब कोई अपीलार्थी इस न्यायालय में एक निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा और द्वारा पुष्टि की गई

उच्च न्यायालय, यह न्यायालय, जैसा कि वर्तमान अपील में पाया जा सकता है कि

मामला दुर्लभतम श्रेणी से कम है और हो सकता है

मृत्युदंड का समर्थन करने में कुछ अनिच्छुक महसूस करें। लेकिन में। उसी समय, अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए,

न्यायालय दृढ़ता से महसूस कर सकता है कि आजीवन कारावास की सजा छूट के अधीन कारावास आम तौर पर काम करता है

14 वर्ष की अवधि अत्यधिक असमान होगी और

अपर्याप्त। फिर अदालत को क्या करना चाहिए? अगर अदालत ने विकल्प केवल दो दंडों तक सीमित है, एक सजा।

कारावास, सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए, अधिक नहीं

लुभाया और पाया

स्वयं मृत्युदंड का समर्थन करने पर जोर दिया। इस तरह का कोर्स

यह वास्तव में विनाशकारी होगा। कहीं अधिक न्यायपूर्ण,

उचित और उचित मार्ग का विस्तार करना होगा

विकल्प और वास्तव में, कानूनी रूप से क्या लेना है

न्यायालय मुख्य रूप से विस्तारित विकल्प का सहारा लेगा। क्योंकि मामले के तथ्यों में, 14 साल की सजा

कारावास किसी भी सजा के बराबर नहीं होगा।

(जोर दिया गया)

31 2008 (13) एससीसी 767 [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

92. तदनुसार, यह न्यायालय कारावास की अवधि निर्धारित करने के लिए खुला है, विशेष रूप से उन मामलों में जहां मृत्युदंड को आजीवन कारावास से बदल दिया जाता है। तत्काल मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता को आजीवन कारावास से गुजरना चाहिए

सजा की माफी के बिना बीस साल से कम नहीं।

एफ. निष्कर्ष

93. ऊपर चर्चा किए गए कारणों के लिए, हम पीड़ित के अपहरण और हत्या में याचिकाकर्ता के अपराध पर संदेह करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। द.

दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने के लिए समीक्षा में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग आवश्यक नहीं है। हालाँकि, हम इस संबंध में तर्कों पर ध्यान देते हैं निचली अदालत में अलग से सजा सुनाने की सुनवाई नहीं की गई है और याचिकाकर्ता को मृत्युदंड देने से पहले अपीलीय अदालतों में परिस्थितियों को कम करने पर विचार नहीं किया गया है।

इस तर्क पर विचार करते हुए, अपराध की वीभत्स प्रकृति

केवल 7 वर्ष की आयु के एक छोटे बच्चे की हत्या ने भी हम पर बोझ डाला है और हम यह नहीं पाते हैं कि आजीवन कारावास की सजा, जो आम तौर पर 14 वर्ष की अवधि तक होती है, में आनुपातिक होगी। परिस्थितियाँ।

94. तदनुसार, हम याचिकाकर्ता पर लगाई गई मौत की सजा को बिना किसी राहत या छूट के कम से कम बीस साल के लिए आजीवन कारावास में बदल देते हैं।

95. अलग से, पुलिस निरीक्षक, कम्मपुरम पुलिस स्टेशन, कुड्डालोर जिला, तमिल राज्य को एक नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है।

26 सितंबर 2021 को हलफनामा दाखिल करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए, इस बारे में स्पष्टीकरण देना है। इस मामले में, प्रथम

में याचिकाकर्ता के आचरण के बारे में भौतिक जानकारी

जेल को इस अदालत से छुपाया गया था। तदनुसार, रजिस्ट्री है

अवमानना के लिए मामले को स्वतः संज्ञान कार्यवाही के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया गया अदालत से।

96. हम समीक्षा याचिकाओं का उपरोक्त शर्तों में निपटारा करते हैं।

निपटाई गई

याचिकाओं की समीक्षा करें।

निधि जैन (तमन्ना, एलसीआरए द्वारा सहायता प्राप्त)

